



पेज 09 में...

बस्तर आकर ऐसा लग रहा जैसे मैं अपने घर आई हूँ: राष्ट्रपति

साप्ताहिक

शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 09 फरवरी से 15 फरवरी 2026

हम दिखाएंगे आईना...



पेज 09 में...

माओवादी का आत्मसमर्पण, शांति की दिशा में बड़ा कदम

वर्ष : 01 अंक : 49 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रूपए

www.shaharsatta.com



पेज

04

एससीआर प्राधिकरण में सीईओ की नियुक्ति लटकी

बस एक चिंगारी और धधक उठेंगी फैक्ट्रियां...

भनपुरी-उरला इंडस्ट्रियल एरिया में पानी का नहीं कोई रोडमैप

रायपुर, बिरगांव, शारडा एनर्जी, अडाणी, भिलाई फायर ब्रिगेड सहारा

डामर फैक्ट्री में भीषण आग, धमाकों के बीच 8 घंटे बाद नियंत्रण

भनपुरी में 15 दमकल वाहन और 50 से ज्यादा कर्मी जूझते रहे

कलेक्टर, डीसीपी, निगम कमिश्नर, डायरेक्टर होमगार्ड चिंतित

तेज गर्मी में इंडस्ट्रियल एरिया में आग का खतरा बनेगा चुनौती



मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

बस एक चिंगारी और उरला, भनपुरी समेत राजधानी रायपुर के औद्योगिक इलाके धधक उठेंगे। दमकल विभाग और एसडीआरएफ समेत होमगार्ड का दम फूल जाता है किसी एक बड़ी फैक्ट्री या कारखानों में लगी आग बुझाने। इंडस्ट्रियल एरिया में गिरते भू-जल स्तर को सम्हालने से लेकर हादसों वाली आग बुझाने के लिए पानी की उपलब्धता का किसी के पास कोई पुख्ता रोडमैप नहीं है।

रायपुर। खमतलाई थाना क्षेत्र में भनपुरी स्थित एक टार (डामर) प्रोडक्ट फैक्ट्री में शनिवार दोपहर 12 बजे आग लग गई। तारकोल, ऑयल और केमिकल से भरे ड्रम वहां रखे होने से आग तेजी से फैली और आधे घंटे के भीतर पूरी फैक्ट्री को लपटों ने घेर लिया। रह रहकर केमिकल के ड्रमों में हो रहे धमाके के कारण भी रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत होती रही। फायर ब्रिगेड व पुलिस को सूचना मिलते ही कई स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किए गए। आसपास के हिस्से को खाली कराकर न केवल नगर सेना के दमकल वाहन, बल्कि तीन-चार औद्योगिक इकाइयों से भी गाड़ियां बुलाई गईं। 15 से ज्यादा दमकल वाहन और 50 से ज्यादा फायर फाइटरों ने 8 घंटे की मशकत के बाद आग पर काबू पाया।

फैक्ट्री के भीतर रखा है क्या, फायर फाइटरों को कोई बताने वाला नहीं:

आग की भयावहता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि 3 घंटे बाद भी फायर फाइटर फैक्ट्री के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। बीस से ज्यादा फायर फाइटर खुद ऑपरेशन के दौरान खतरे में थे क्योंकि उन्हें फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से कोई यह बताने वाला तक नहीं मिला कि भीतर क्या-क्या रखा है।

आग के शुरूआती दो घंटे के भीतर तीन बड़े धमाके भी हुए, जिसमें फायर फाइटर बाल-बाल बचे। हालांकि 3 घंटे बाद

आग को फैलने से रोक लिया गया लेकिन उसे बुझाने का काम 8-9 बजे भी जारी रहा। इस बीच गोदावरी, हीरा ग्रुप समेत अन्य फैक्ट्रियों से भी दमकल वाहन मंगा लिए गए। भीतर टार प्रोडक्ट, ऑयल-केमिकल जैसे ज्वलनशील पदार्थ भरे हुए थे इसलिए आग बुझाने में काफी वक्त लगा। शाम को पांच बजे तक धुएं का गुबार इतना ज्यादा उठता रहा कि उसे 20 किमी दूर धरसीवा, मंदिरहसौद, कुम्हारी और माना कैम्प से भी देखा गया।

कचरा जलाने के दौरान फैली आग, होगी एफआईआर

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह, डीसीपी मयंक गुर्जर, आपदा प्रबंधन होमगार्ड डायरेक्टर आईपीएस चंद्रमोहन सिंह, निगम कमिश्नर विश्वदीप खुद मौके पर डटे रहे। कलेक्टर गौरव सिंह ने एफआईआर दर्ज करके जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस के मुताबिक आगजनी की वजह जांच में सामने आएगी। लेकिन शुरुआती पूछताछ में पता चला कि सुबह साफ-सफाई के बाद फैक्ट्री कैम्पस में एकत्रित कचरे को जलाने का प्रयास किया गया था। आग की भयावहता को देखते ही पुलिस लाइन से भी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त अधिकारी व बल भेजे गए। फैक्ट्री एरिया खाली कराकर आसपास आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई।

“
फैक्ट्री की आग 8 घंटे बाद काबू में आई। रेस्क्यू स्टाफ खतरे में था क्योंकि फैक्ट्री के भीतर किस हिस्से में क्या है, कोई बताने वाला नहीं था। लगातार दो इमों में धमाका हुआ तो रेस्क्यू टीम को पीछे हटाकर ऑपरेशन तेज कराया गया।

पुष्पराज सिंह, जिला सेनानी होमगार्ड रायपुर

“
प्लांट में सेप्टी का ध्यान नहीं रखे जाने और कचरा जलाने से आग लगी है। आसपास काफी संख्या में फैक्ट्रियां हैं, वहां भी आग फैलने का खतरा था। फैक्ट्री प्रबंधन से जुड़े लोग और स्टाफ से जल्द पूछताछ करके कड़ी कार्रवाई करेंगे।

मयंक गुर्जर, डीसीपी नार्थ पुलिस कमिश्नरी जोन रायपुर

तीसरी बार आगजनी की घटना

रायपुर आसपास के रहवासियों के अनुसार फैक्ट्री में तीसरी बार आगजनी की घटना हुई है। इसके पूर्व दो बार टार फैक्ट्री आग की चपेट में आ चुका है। आग से कितना का बुकसान हुआ है, इस बात की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। जाम के पूरी तरह से बुझाने के बाद ही नुकसान का सही अंदाजा लग सकता है। पुलिस तथा फायर ब्रिगेड को टीम आम लगने के कारणों के बारे में जानकारी जुटा रही है। टार फैक्ट्री में लगी आग से उठ रही लपटें तथा विस्फोट से आसपास के फैक्ट्री संचालक दहशत में रहे। आसपास के फैक्ट्री संचालक सात घंटे तक दहशत के साये में रहे। फैक्ट्री में जिस स्तर का धमाका हो

रहा था, उससे ऐसा लग रहा था, फैक्ट्री से निकली चिंगारी अन्य उद्योगों को अपनी चपेट में ले लेगी। आग पर काबू पाने रायपुर, बिरगांव नगर निगम के साथ शारडा एनर्जी, अडाणी के साथ भिलाई से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ीं, तब कहीं जाकर देर शाम आग पर काबू पाया जा सका। टार फैक्ट्री में लगी आग से धुएं के गुबार को भनपुरी, उरला के साथ राजधानी तक देखा गया। हवा की दिशा रायपुर की तरफ होने की वजह से धुएं का गुबार तेलीबांधा तक देखा गया। उठ रहे धुएं के गुबार को देखकर ऐसा लग रहा था, मानो आग शहर के किसी व्यस्त इलाके में लगी हो।

पानी की दिक्कतों से अफसरों की टीम हुई दो-चार



आग बढ़ने की जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी मयंक गुर्जर, एडीसीपी आकाश मरकाम सहित अन्य पुलिस अफसरों के साथ जिला पंचायत के सीईओ, बिरगांव नगर निगम के कमिश्नर सहित अन्य अफसर मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लेते हुए राहत तथा बचाव कार्य के लिए दिशा निर्देश दिए। घटना स्थल पर किसी भी तरह की अनहोनी रोकने तीन एंबुलेंस की टीम बुलाई गई थी। दमकल वाहनों का पानी खत्म होने के बाद पानी की किल्लत और उपलब्धता की दिक्कत से भी अधिकारी दो-चार हुए। आखिरकार बड़े उद्योगों से मदद ली गई।

प्रत्यक्षदर्शी ने बताया ऐसे लगी आग एक अन्य फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी शिवम सोनी ने बताया कि वह रायपुर टार फैक्ट्री से सटी एक अन्य फैक्ट्री में वह टिफिन छोड़ने के लिए आया था। जिस फैक्ट्री में आगजनी की घटना घटित हुई है, उस फैक्ट्री के नजदीक एक अन्य फैक्ट्री में काम चल रहा था। जिस फैक्ट्री में काम चल रहा था, वहां के मजदूर ऊंचाई पर चढ़कर वेल्डिंग का काम कर रहे थे। इस दौरान वेल्डिंग के दौरान चिंगारी टार फैक्ट्री के ऑयल में गिरी। वेल्डिंग की चिंगारी गिरने से टार फैक्ट्री में एक सीमित जगह में आ लगी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया।

आवाजाही रोक दी गई

पुलिस की टीम ने फैक्ट्री पहुंचने के मार्ग को आता की भयावहता को देखते हुए मौके पर पहुंची रस्सी से घेरकर दोनों तरफ रौ-सौ मीटर के दायरे में ताड़ियों की आवाजाही बंद कर दी। आशंका जताई जा रही थी कि ऑयल से भरे टैंकर में विस्फोट होने से आग की लपटें सौ मीटर के दायरे में फैल सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से सौ मीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही रोक दी थी।



नियंत्रण नहीं होने से स्थिति भयावह होती

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फैक्ट्री के अंदर सौ से ज्यादा ड्रम तथा बड़े टैंकरों में टार ऑयल स्टोर किया गया था। इसके कारण आग पर काबू पाने फायर ब्रिगेड की टीम को परेशानी का कामना करना पड़ रहा था। फायर ब्रिगेड की टीम एक हिस्से में जहां आग पर काबू पाती, दूसरे छोर पर धमाका होकर आता की लपटें उठने लगतीं और देखते ही देखते धुएं का गुबार उठने लगता। काले धुएं की वजह से कुछ दिखाई नहीं देता था। इस वजह से दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।

छत्तीसगढ़ में हो रहा 49.58 भूजल का दोहन

केंद्रीय जल मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में औसत भूजल दोहन 49.58 प्रतिशत दर्ज किया गया है। ये भूजल दोहन प्रदेश में तब हो रहा है, जब औसतन बारिश 1266.9 मिमी होती है। बारिश के पानी को सिंचित करने और भूजल पुनर्भरण करने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा ये स्थिति और भी खतरनाक होगी।

डेढ़ महीने में ही भूजल 1.20 मीटर लुढ़का

अप्रैल की भीषण गर्मी ने जिले में पानी के लिए जद्दोजहद शुरू कर दी है। जिले के 623 गांवों में से 155 गांवों को पीएचई विभाग ने जल संकटग्रस्त घोषित किया है। 6 नल-जल योजनाएं पूरी तरह ठप हो चुकी हैं। डेढ़ महीने में भूजल स्तर 1.20 मीटर गिरा है। इसका कारण अंधाधुंध रेत खनन और पानी का बेतहाशा दोहन है। पिछले साल गर्मी में जलस्तर में 4.5 मीटर तक गिरावट दर्ज हुई थी। इस साल जिले का औसत जलस्तर 17.70 मीटर से घटकर 18.90 मीटर पर पहुंच गया है। 1.20 मीटर की गिरावट अब तक सामने आई है। जलस्तर गिरने से 457 मोटर पंप और हैंडपंप बंद हो चुके हैं। कई गांवों में तालाब और कुएं भी सूख चुके हैं।

जल संकट की खास वजह

- भूजल का अत्यधिक दोहन
- कृषि, उद्योग और घरेलू जरूरतों के लिए बेतहाशा बोरवेल और ट्यूबवेल से पानी निकाला गया।
- recharge की तुलना में खपत कई गुना अधिक हो गई।
- जल संरक्षण ढांचों की उपेक्षा: तालाब, जोहड़, छोटे बाँध और नहरें उपेक्षित हैं।
- कई जलाशयों की सिल्टिंग (कीचड़ जमाव) ने उनकी क्षमता घटा दी है।
- वनों की कटाई और शहरीकरण: पेड़ कम होने से जल धारण क्षमता घटी है।
- कंक्रीट के जंगलों ने जमीन में पानी रिसने की प्राकृतिक प्रक्रिया को बाधित किया है।
- वाष्पीकरण की दर में भारी बढ़ोतरी: अधिक गर्मी और ग्लोबल वार्मिंग के चलते जलाशयों से पानी तेजी से भाप बनकर उड़ रहा है।
- 300% तक की वाष्पीकरण दर बढ़ी चुनौती बन गई है।



‘दफ्तर में आग’ पर आबकारी विभाग का दावा, कंप्यूटर-प्रिंटर जले हैं, फाइलों-दस्तावेजों को कोई नुकसान नहीं

शहर सत्ता/रायपुर। आबकारी भवन के तीसरे माले पर शनिवार-रविवार की दरमियानी रात आग लगने और दस्तावेज जलने के मामले में आबकारी अफसरों की आज दिनभर खामोशी के बाद शाम करीब 7 बजे आला अफसरों के निर्देश के बाद विभाग की तरफ से अधिकृत बयान जारी हुआ है। आबकारी विभाग ने इस बयान में कहा है कि आग से कंप्यूटर, प्रिंटर और यूपीएस वगैरह जले हैं। सारे दस्तावेज अलमारी में रहने के कारण सुरक्षित हैं।

आबकारी विभाग की ओर से जारी किया गया अधिकृत बयान इस तरह है- दिनांक 07/02/2026 को रात लगभग 8:30 बजे लाभाण्डी स्थित आबकारी भवन में छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड के कार्यालय के तृतीय तल के एक कक्ष में बिजली के शार्ट सर्किट से आग लगने से कार्यालय में रखा कंप्यूटर, प्रिंटर और युपीएस जल गया है। अवलोकन से दस्तावेजों को कोई नुकसान नहीं होना पाया गया है। सभी फाइल नस्ती लोहे आलमारी में बंद थीं। रात्रि में आबकारी भवन में ड्यूटी पर तैनात गार्ड को तृतीय तल के एक कक्ष में कुछ



जलने जैसी गन्ध आने पर तत्काल अन्य स्टॉफ को बुलाया और तत्काल मौके पर पहुंचकर कर भवन में मौजूद अग्निरोधक उपकरणों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर मुआयना करने पर आग से कार्यालय में रखे प्रिंटर और यूपीएस का जलना पाया गया। आग से किसी अन्य सामग्री का या अन्य किसी कक्ष में कोई नुकसान नहीं हुआ है। खबर मिलते ही तत्काल उच्च अधिकारियों द्वारा मौके पर



पहुंचकर अवलोकन किया गया। दिनांक 08/02/2026, रविवार को सुबह पुनः अधिकारियों द्वारा पहुंच कर अवलोकन करने पर किसी भी जरूरी दस्तावेज का उक्त घटना में नुकसान नहीं होना पाया गया।



शोएब डेबर का एक और वीडियो वायरल, बुजुर्ग से गाली- गलौज

रायपुर। राजधानी रायपुर में एक वीडियो वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में शोएब डेबर कथित तौर पर बीच सड़क एक बुजुर्ग व्यक्ति से अभद्र भाषा में बात करते और गाली-गलौज करते दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो एक-दो दिन पुराना है। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से फैलने के बाद लोग कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठा रहे हैं। तेलीबांधा क्षेत्रांतर्गत व्ही.आई.पी. रोड स्थित राम मंदिर के सामने आरोपी शोएब डेबर द्वारा वाहन चलाते समय प्रार्थी आर.बी. मिश्रा की कार को क्षति (स्क्रैच) पहुँचाई गई।

इस संबंध में प्रार्थी द्वारा आपत्ति करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थी के साथ अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त घटना से संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

दोस्ती की और ऑनलाइन लोन का झांसा देकर नाइट चौपाटी वेंडरों से ठगे 20 लाख

रायपुर। ऑनलाइन फाइनेंस और प्री अप्रूव्ड लोन की आड़ में एमजी रोड की नाइट चौपाटी के आधा दर्जन कारोबारियों के साथ लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। कारोबारियों के आधार कार्ड, फोटो समेत अन्य दस्तावेज लेकर उनके नाम पर करीब 20 लाख के लोन मंजूर कराकर रकम अपने खाते में ट्रांसफर कराने वाले 19 वर्षीय आरोपी मुदित पाठे उर्फ कृष पवार पिता विजय कुमार पाठे को गिरफ्तार किया गया है। छिंदवाड़ा निवासी यह आरोपी काम की तलाश में रायपुर आया और एक होटल में रूककर फ्रॉड को अंजाम दिया। हालांकि उससे रकम बरामद नहीं की जा सकी है। उसने अपने परिचितों और परिजनों के एकाउंट में फ्रॉड की रकम ट्रांसफर कर दी है।



पुलिस के पास अभी केवल एक कारोबारी दौलत कुशवाहा पहुंचा है। उसके नाम पर 3.84 लाख रुपए का लोन लिया गया है। मौदहापारा पुलिस थारा 318 (4) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुदित पाठे उर्फ कृष पवार ट्रेन से फरार होने की तैयारी कर चुका था। इसकी भनक लगते ही उसे दबोचा गया। आरोपी 10वीं पास है और छह महीने पहले फाइनेंस सेक्टर में कार्य करने की इच्छा लेकर रायपुर आया था। पिता बीमा सेक्टर में थे इसलिए उसे भी फायनेंस के बारे में कई तरह की जानकारियां थीं। एक लॉज की डोरमेट्री में ठहरकर ठेले वालों एवं छोटे व्यापारियों से धीरे-धीरे मेलजोल बढ़ाया। कभी उनका बिजली बिल ऑनलाइन जमा करके या मोबाइल लोन मंजूर कराकर उनकी मदद करता था। उन्हें ऑनलाइन फाइनेंस, कैश बैंक एवं इनवेस्टमेंट एप्स से बेस्ट कैश बैंक, प्रोमो

कोड एवं रेफरल कोड की जानकारी लेकर उन्हें कैशबैंक भी दिलाया। इसके लिए वह पीड़ितों का मोबाइल फोन लेता रहा है। लोन मंजूर कराने के लिए भी उसने उन्हीं के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। मोबाइल से ही राशि को अपने ऑनलाइन वॉलेट एवं अन्य खातों में चैनलाइज किया।

बैंक से आए किस्त के लिए फोन, तब लगी खबर

आधा दर्जन पीड़ितों को हाल ही में बैंकों से फोन आया कि उनके लोन की किस्त जमा नहीं हुई है। पता चला कि दो महीने पहले लोन लिए गए और उसकी शुरुआती किस्त आरोपी ने खुद भरी। इसके बाद जब किस्त जमा नहीं हुई तो पीड़ितों को बैंक से फोन गए, तब लघु कारोबारियों को धोखाधड़ी का पता लगा और वे शिकायत करने पहुंचे। एडिशनल डीसीपी कोतवाली दीपक मिश्रा के मुताबिक आरोपी द्वारा छिंदवाड़ा में भी इसी तरह फ्रॉड करने की आशंका है। पुलिस पता लगा रही है कि फ्रॉड की रकम जिनके खाते में गई है, उनकी अपराध में सहभागिता है या नहीं।



क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक और मोबाइल फोन बरामद

आरोपी से दर्जनभर बैंक कार्ड्स क्रेडिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक तथा मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आईडीएफसी, एक्सिस, एयू स्माल फाइनेंस बैंक, यूनिटी स्माल फाइनेंस बैंक से लोन मंजूर कराया गया है। रिश्तेदारों के एकाउंट में रकम ट्रांसफर फर हुई है। आशंका है कि परिचितों के एकाउंट को म्यूल एकाउंट की तरह यूज किया है। रकम सीज करने की प्रक्रिया जारी है।

उमेश प्रसाद गुप्ता, डीसीपी सेंट्रल कमिश्नरी रायपुर

20 बड़े बकायादारों की दुकानें सील



रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम के आयुक्त विश्वदीप के आदेशानुसार और अपर आयुक्त राजस्व कृष्णा खटीक, उपायुक्त राजस्व जागृति साहू और जोन 8 जोन कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देशानुसार एवं कार्यपालन अभियंता अतुल चोपड़ा और जोन 8 सहायक राजस्व अधिकारी महादेव रक्सेल के नेतृत्व और राजस्व निरीक्षक राजेश मिश्रा, सहायक राजस्व निरीक्षक खगेंद्र सोनी, राम कुमार अवसर, चंदन रगड़े की उपस्थिति में नगर पालिक निगम जोन 8 की राजस्व विभाग की टीम द्वारा नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 क्षेत्र अंतर्गत 20

बड़े बकायादारों द्वारा विगत कई वर्षों से बकाया राशि नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा डिमांड बिल डिमांड नोटिस एवं अंतिम नोटिस जारी करने के उपरांत भी नगर निगम जोन 8 राजस्व विभाग को बकाया राशि अदा नहीं करने पर अभियान चलाकर संबंधित 20 बड़े बकायादारों के 20 व्यवसायिक परिसरों को तत्काल ताला लगाकर सीलबंद करने की कड़ी कार्यवाही की गयी है।

रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 8 जोन कमिश्नर श्रीमती राजेश्वरी पटेल एवं सहायक राजस्व अधिकारी श्री महादेव रक्सेल ने बताया कि आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन 8 राजस्व विभाग द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत वीर सावरकर नगर वार्ड क्रमांक 1 अंतर्गत 526273 रु. के बकायेदार प्रितम सिंग जीत सिंग, 224509 रु. के बकायेदार अशोक कुमार, विजय कुमार, विनोद कुमार नवानी, 449614 रु. के बकायेदार हरवंश सिंग, महेन्द्र सिंग, सुरजीत कौर वगैरह, 182710 रु. के बकायेदार राहुल धारीवाल, रु. 140257 के बकायेदार आदिल खान, 438529 रु. के बकायेदार प्रमोद अग्रवाल, 133053 रुपये के बकायादार ओमप्रकाश तिवारी, के संबंधित व्यवसायिक परिसर में तत्काल ताला लगाकर सीलबंदी की कार्यवाही बकाया राशि राजस्व विभाग को अदा नहीं करने पर की गई है।

एम्स में नकली असिस्टेंट प्रोफेसर युवक युवती पकड़ाए छह माह से घूम रहे थे

रायपुर। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के असिस्टेंट प्रोफेसर की फर्जी आईडी के साथ एप्रन पहने एक युवक एवं युवती को पकड़ा गया है। बताया गया कि नकली असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर घूमने वाला युवक पिछले 6 महीने से अस्पताल के सभी विभागों के साथ ब्लड कलेक्शन सेंटर में रोजाना आकर बैठ रहा था। वहीं महिला को अक्सर ट्रामा यूनिट और पीडियाट्रिक वार्ड के अलावा स्त्री रोग विभाग में देखा जाता था। संदेह होने पर शुक्रवार को एम्स के सुरक्षा गार्ड सूर्यकांत एम्स मिश्रा और डीएनएस प्रदीप कुमार जेवका ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ब्लड कलेक्शन सेंटर में युवक को एप्रन पहने घूमते देख संदेह प्रभारी श्री जेवका ने पूछताछ की तो उसने अपने आपको पिछले डेढ़ साल से रेडियोडायग्नोसिस विभाग में टेक्निशियन के पद पर काम करना बताया। मौके पर जब विभागाध्यक्ष का सामना युवक से कराया



गया तो उसकी पोल खुल गई। पुलिस ने युवक की तलाशी ली तो एम्स की फर्जी आईडी में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. दुर्जन सिंग गोयल का नाम पाया गया। इसकी सूचना कार्यपालक निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अशोक जिंदल (रिटायर्ड) को देने के बाद फ्रॉड युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। श्री जिंदल ने कहा कि एम्स रायपुर एक प्रमुख टसरी हेल्थकेयर एवं शैक्षणिक संस्थान है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज एवं उनके परिजन इलाज के लिए आते हैं।

पाठक का कोना



हमारे बुजुर्ग आसिफ अली यूसुफी सदर बाजार, शहर सत्ता अखबार का हर अंक बड़े शौक से पढ़ते हैं

एक साल में ही फैसला हत्यारे पति को उम्रकैद

रायपुर। चरित्र शंका में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने पर न्यायाधीश ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक साल में ही आरोप सिद्ध होने पर आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 2 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत मृतका के माता-पिता को क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश भी दिया है।

यह मामला गरियाबंद जिले के थाना पांडुका का है। इस मामले में अंतिम सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट पंकज कुमार सिन्हा के कोर्ट में पूर्ण हुई। इस मामले की पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक उमा शंकर वर्मा ने बताया कि अभियुक्त सोहन राम साहू ने मृतिका ओमिका धुव से प्रेम विवाह किया था। उसकी पत्नी होमगार्ड की नौकरी में थी। शादी के कुछ माह बाद ही अभियुक्त पत्नी पर चरित्र शंका करने लगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई वाद विवाद भी हुआ। 12 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 8 बजे पत्नी को बाइक पर बैठकर सरगी नाला रोड के पास जंगल में ले जाकर हत्या कर दी। पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी जेल में रिमांड पर रहा।



• **माता-पिता को क्षतिपूर्ति राशि देने का भी आदेश**

पुलिस ने घटनास्थल पर मिले साक्ष्य, पीएम रिपोर्ट और आरोपियों के बयान कोर्ट में पेश किये। अभियोजक द्वारा कोर्ट से निवेदन किया गया कि अभियुक्त ने गंभीर अपराध किया है। अधिकतम दंड से दंडित किया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्य और सबूतों के आधार पर अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास और 2000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

बकायादारों के नलों के कनेक्शन काटे

रायपुर। जोन 4 राजस्व कर्मचारियों की स्थल पर उपस्थिति में नगर पालिक निगम जोन 4 की राजस्व विभाग की टीम द्वारा नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 4 अंतर्गत डॉ विपिन बिहारी सूर वार्ड क्रमांक 64, स्वामी विवेकानंद सदर बाजार वार्ड क्रमांक 44, पण्डित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 34, सिविल लाईन वार्ड क्रमांक 46 क्षेत्र अंतर्गत कुल 26 बकायादारों द्वारा विगत कई वर्षों से बकाया राशि नगर पालिक निगम रायपुर द्वारा डिमांड बिल डिमांड नोटिस एवं अंतिम नोटिस जारी करने के उपरांत भी नगर निगम जोन 4 राजस्व विभाग को बकाया राशि अदा नहीं करने पर अभियान चलाकर संबंधित 26 बकायादारों पर बकाया वसूलने नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की गयी।

रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 4 जोन कमिश्नर अरुण धुव एवं सहायक राजस्व अधिकारी अमरनाथ साहू ने बताया कि आज रायपुर नगर पालिक निगम जोन 4 राजस्व विभाग द्वारा जोन क्षेत्र अंतर्गत डॉ विपिन बिहारी सूर वार्ड क्रमांक 64 अंतर्गत 72999 रु. के बकायेदार दुलारी यादव का नल बकाया अदा नहीं करने पर विच्छेद करने की कार्यवाही की

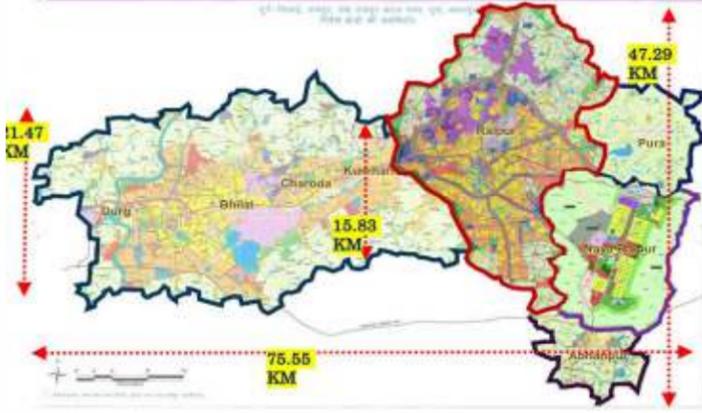


गयी, इसी प्रकार नगर निगम जोन 4 राजस्व विभाग को बकाया कर अदा नहीं किये जाने पर 325936 रु. के बकायेदार अनिल सिंग, अर्जन सिंग, तालिक सिंग ठाकुर, 90271 रु. के बकायादार गोपाल प्रसाद दुबे, 42215 रु. के बकायादार मनिया सेन्ट्रे, 26487 रु. के बकायादार जीवनलाल सोनी, 63090 रु. के बकायादार सीता बाई यदु का नल विच्छेद करने की कड़ी कार्यवाही की गयी।

एससीआर प्राधिकरण में सीईओ की नियुक्ति लटकी

सीएम की अध्यक्षता में गठित हो चुका संचालक मंडल, क्षेत्र अधिसूचित करने सर्वे, इकोनॉमिक मास्टर प्लान भी

रायपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर, नवा रायपुर व दुर्ग-भिलाई को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन (एससीआर) विकसित करने की कवायद फिलहाल धीमी हो गई है। छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति अब तक नहीं हो पाई है। इसके चलते एससीआर का काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संचालक मंडल का गठन पहले ही किया जा चुका है। संचालक मंडल की पहली बैठक के लिए सीईओ की पदस्थापना का इंतजार है। आवास व पर्यावरण विभाग ने बैठक का एजेंडा भी तैयार कर लिया है। सीईओ की पदस्थापना के बाद संचालक मंडल की पहली बैठक होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले होंगे। प्रस्तावित एजेंडे में एससीआर का एरिया तय करने व सर्वे के लिए कंसल्टेंसी तथा नवा रायपुर-रायपुर दुर्ग-भिलाई मेट्रो रेल परियोजना के डीपीआर के लिए सलाहकार संस्था का चयन आदि शामिल है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास



प्राधिकरण के सेटअप के लिए 210 पदों की मंजूरी पूर्व में मिल चुकी है। वहीं, प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति की फाइल भी अनुमोदन के लिए मुख्य सचिव को पखवाड़े भर पहले भेज दी गई है, लेकिन शासन द्वारा अभी सीईओ की पदस्थापना नहीं की गई है। बताया गया है कि एससीआर के सफल क्रियान्वयन के लिए किसी वरिष्ठ व अनुभवी आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकता है। एससीआर का मुख्यालय नवा रायपुर में रहेगा। गौरतलब है

कि छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र की योजना, समन्वय, पर्यवेक्षण, प्रोत्साहन व विकास को सुनिश्चित करने तथा उसके संबंध या आनुषंगिक विषयों के संबंध में निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित संचालक मंडल में सदस्य के रूप में आवास मंत्री, नगरीय प्रशासन मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, मुख्य सचिव, आवास सचिव, नगरीय प्रशासन सचिव, पीडब्ल्यूडी सचिव व वित्त सचिव शामिल हैं। मुख्य

कार्यपालन अधिकारी को संचालक मंडल में सदस्य संयोजक बनाया गया है। मेट्रो के लिए फिजिबिलिटी स्टडी नवा रायपुर-रायपुर-भिलाई-दुर्ग मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए दिल्ली की जॉइंट फर्म केपीएमजी व अर्बन मास ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड को सलाहकार नियुक्त किया गया है।

इकोनॉमिक मास्टर प्लान

एससीआर का एरिया तय करने के लिए कंसल्टेंसी चयन की प्रक्रिया चल रही है। चयनित कंसल्टेंसी फर्म एससीआर के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का सेनेरियो एनालिसिस (परिदृश्य विश्लेषण) कर विस्तृत इकोनॉमिक मास्टर प्लान तैयार करेगी। इनमें महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, जमीन की उपयोगिता, इंटरियल पार्क व सड़क इत्यादि शामिल हैं। एससीआर में वर्ष 2031 तक 50 लाख की आबादी अनुमानित है। राज्य बजट में एससीआर कार्यालय, सर्वे व डीपीआर तैयार करने के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। राजधानी क्षेत्र के विकास का रोडमैप भी तैयार किया जाएगा।

अत्याधुनिक

अधोसंरचना का विकास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर एससीआर का खाका तैयार किया गया है। एससीआर छत्तीसगढ़ का नया ग्रोथ इंजन होगा। दिल्ली-एनसीआर की तर्ज पर ही एससीआर में भी अत्याधुनिक अधोसंरचना, व्यापार व शिक्षा-स्वास्थ्य केन्द्र विकसित किए जाएंगे।

एससीआर में 6 हजार

वर्ग किमी क्षेत्र

एससीआर में रायपुर, नवा रायपुर व भिलाई-दुर्ग सहित आसपास के करीब 6000 वर्ग किमी क्षेत्र शामिल होंगे। बाद में राजनांदगांव तक एससीआर का विस्तार किया जा सकता है। एससीआर का क्षेत्र अधिसूचित किए जाने बाद कई अधोसंरचना विकास से संबंधित गतिविधियों में तेजी आएगी।

पहली बार कर्तव्य भवन में बना बजट : खट्टर

केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर पहुंचे रायपुर कहा- छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए केंद्र प्रतिबद्ध



शहर सत्ता/रायपुर। केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने केन्द्रीय बजट को नवोत्थान और समावेशी विकास का वाहक बताते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत-2047 के दीर्घकालिक विजन को साकार करने वाला एक सशक्त दस्तावेज है। वे राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रवास के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय मंत्री लाल ने कहा कि इस बजट में अगले 25 वर्षों के लिए देश के आर्थिक, सामाजिक एवं बुनियादी ढांचे के विकास की स्पष्ट दिशा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह बजट पहली बार कर्तव्य भवन में तैयार किया गया है,

जो शासन व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। बजट में 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी सम्मिलित किया गया है, जिससे आगामी वर्षों में राज्यों के विकास को नई गति मिलेगी। मनोहर लाल ने विश्वास जताया कि बजट प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन से बिजली, आवास, शहरी विकास एवं अधोसंरचना क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील और प्रतिबद्ध है। प्रेस वार्ता में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू, प्रदेश के वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद संतोष पाण्डेय एवं बृजमोहन अग्रवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रेरा के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए 14 बैंकों का फायनल इम्पैनलमेंट



रायपुर। छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण, रेरा ने राज्य में रियल एस्टेट के प्रावधानों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए पहल की है। इस क्षेत्र में पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन और रियल एस्टेट अधिनियम के प्रभावी अनुपालन के लिए 14 बैंकों को अंतिम पैनल में शामिल किया है। बीते 3 अप्रैल 2025 को 17 बैंकों को अस्थायी पैनल में शामिल किया गया था। निर्धारित प्रक्रियाओं, आवश्यक शर्तों एवं मापदंडों की पूर्ति के बाद अब इनमें से 14 बैंकों को पैनल में शामिल किया गया है।

अंतिम पैनल में शामिल बैंकों में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, केनरा बैंक, डीसीबी बैंक, फेडरल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एवं सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक शामिल हैं। इस पहल के

जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजनाओं से संबंधित पृथक रेरा खाते केवल उन्हीं बैंकों में संचालित किए जाएं, जो रेरा नियमों एवं दिशा-निर्देशों का पूर्णतः पालन करते हों। इससे परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में अनुशासन स्थापित होगा।

निधियों के उपयोग में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा घर खरीदारों के हितों की प्रभावी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष संजय शुक्ला ने कहा कि रेरा की पंजीकृत परियोजनाओं में वित्तीय अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना प्राधिकरण की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। बैंकों के अंतिम पैनल में शामिल होने से परियोजना खातों की निगरानी एवं नियंत्रण व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी, जिससे घर खरीदारों का विश्वास बढ़ेगा।

सेक्टर 24 में 1.5 लाख वर्गफीट क्षेत्र में निर्माणाधीन 2 साल के भीतर भवन बनकर तैयार होगा

नवा रायपुर में 169 करोड़ की लागत से बन रहा 11 मंजिला 'आयोग भवन'

रायपुर। नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में शासकीय विभागों, आयोगों व निगमों के कार्यालयों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन का निर्माण किया जा रहा है। यह आयोग भवन कहलाएगा और 11 मंजिला होगा। इस एक ही बिल्डिंग में सभी 33 आयोगों के दफ्तर रहेंगे। करीब 169 करोड़ रुपए की लागत से डेढ़ लाख वर्गफीट क्षेत्र में बनने वाले इस बहुमंजिला भवन में वाहन पार्किंग व लिफ्ट सहित अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं रहेंगी।

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि भवन निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसका ठेका डीवी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह वही कंपनी है,



जिसके द्वारा नवा रायपुर में नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया गया है। नवा रायपुर में निर्माणाधीन आयोग भवन दिसंबर 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा।

इसके बाद इस आयोग भवन में विभिन्न विभागों को आयोगों के दफ्तर के लिए स्पेस आबंटित किया जाएगा, ताकि भूमि का पूर्ण उपयोग किया जा सके। वर्तमान में राज्य शासन के अंतर्गत विभिन्न आयोगों के दफ्तर अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रहे हैं। एक ही भवन में सभी आयोगों के दफ्तर होने से आम लोगों को भी सुविधा होगी। नवा रायपुर सेक्टर 24 में अन्य प्रशासनिक भवन, केंद्रीय कार्यालय व आवासीय प्रोजेक्ट भी स्थित हैं।

कॉमर्शियल टॉवर के बाजू में 'आईटी भवन'

नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-21 स्थित कॉमर्शियल टॉवर के बाजू में नए आईटी भवन का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से लगभग डेढ़ लाख वर्गफीट क्षेत्र में निर्माणाधीन यह आईटी भवन भी 11 मंजिला रहेगा। भवन में आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को ऑफिस स्पेस आवंटित किया जाएगा। इस भवन का निर्माण नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है और दो साल के भीतर इसका निर्माण कार्य पूरा होने की उम्मीद है। इसे नवा रायपुर को देश का अगला आईटी हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आईटी भवन में अंतरराष्ट्रीय आईटी कंपनियों के ऑफिस शुरू होने से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि आईटी और सर्विस सेक्टर की कंपनियों के आने से छत्तीसगढ़ की पहचान बदल रही है। छत्तीसगढ़ अब टेक्नोलॉजी, नवाचार व सेवा क्षेत्र का भी एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है।

संपादकीय

• सुकांत राजपूत



नीर क्षीर

यह सही है कि सरकार की ओर से जल संरक्षण को लेकर कई कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं तो उनका मकसद चुनौतियों से पार पाना ही है। लेकिन यह भी सच है कि स्थानीय हालात और जरूरतों के आधार पर अगर कोई पहलकदमी होती है, तभी इस संकट से पार पाने की उम्मीद की जा सकती है।

दरअसल, भूजल के स्तर को लेकर चिंता लंबे समय जताई जाती रही है, लेकिन इस गहराती समस्या से निपटा कैसे जाए, इसकी दिशा अभी पूरी तरह साफ नहीं रही है। न केवल वर्षा से जल के संरक्षण के पहलू पर कोई बड़ी कार्ययोजना जमीन पर नहीं उतर पाई है, न अन्य स्रोतों की वास्तविक स्थिति का आकलन करके उसके समाधान को लेकर ठोस पहल हुई है। हालांकि 'अटल भूजल योजना' डबरी योजना, नल-जल मिशन एक हद तक ही बेहतर गुंजाईश की पैरोकार है। लेकिन गिरते भू-जल स्तर पर या बढ़ते उद्योग के लिए पानी की व्यवस्था चुनौती ही नहीं भविष्य की बड़ी जरूरत भी है। करीब छह महीने पहले भी प्रधानमंत्री ने पानी की एक-एक बूंद के संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करने पर जोर दिया था। यह अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि भूजल के स्तर और समग्र पैमाने पर जल की उपलब्धता को लेकर सरकार फिक्रमंद जरूर है, लेकिन शायद एक समग्र योजना के साथ जमीनी अमल अभी बाकी है। समस्या यह है कि भारी पैमाने पर पानी का बेलगाम उपयोग और उसकी बर्बादी करने वाले बड़ी कंपनियों और संस्थानों पर शायद ही किसी की लगाम है। यह गांवों और शहरों में वर्षा जल के संरक्षण को लेकर सजगता नहीं होने और इससे पैदा होने वाली समस्या से इतर एक पहलू है, जिसमें भारी मात्रा में पानी की बर्बादी होती है। सवाल है कि जल संरक्षण को लेकर जताई जाने वाली चिंता के मद्देनजर क्या इस समस्या के बुनियादी पहलुओं पर भी गौर किया जाएगा?

देश में ऐसे तमाम इलाके हैं, जहां भूजल का स्तर चिंताजनक पैमाने तक नीचे चला गया है। इसका एक बड़ा असर फसलों के उत्पादन के चक्र पर पड़ा है, जिसमें सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत वाली फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। हाल के दिनों में यह राय सामने आई है कि सिंचाई के लिए जल के बढ़ते संकट के मद्देनजर कम पानी की जरूरत वाली वैकल्पिक फसलें उगाने और सूक्ष्म सिंचाई की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे देश में पानी के संरक्षण के कई पारंपरिक तौर-तरीके चलन में रहे हैं। लेकिन यह समझना मुश्किल है कि आखिर किन वजहों से हम उन परंपराओं से दूर होते गए। भूजल का गिरता स्तर और इसकी वजह से भविष्य में गहराने वाले संकट के मसले पर पिछले कुछ सालों से लगातार चर्चा होती रही है। इस चिंता के मद्देनजर न केवल भारत, बल्कि वैश्विक पैमाने पर सम्मेलनों और सेमिनारों में आने वाले दिनों में पानी के अभाव को लेकर चेतावनी दी जाती रही है। लेकिन चिंता जताना और संकट का हल निकालना अलग-अलग बातें हैं।

विकसित भारत के केंद्र में इकोनॉमी तो है, पर इंसान?



मुकेश माथुर

शून्य से शिखर तक पहुंचने वाला एक व्यक्ति अपना 'विकास' किसे मानेगा? जैसे, पद, प्रतिष्ठा को या अच्छी गुणवत्ता वाले जीवन-स्तर, बौद्धिक विकास, मन की शांति और खुशी को? इससे भी आगे, अपने दायरे में आने वाले लोगों की जिंदगियां बेहतर करने को? शायद इस सभी को, लेकिन सिर्फ बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी विकास नहीं हो सकता।

2047 में विकसित देश बनने से हमारे देश को कोई नहीं रोक सकता। ट्रम्प का टैरिफ भी नहीं। अब हमारे पास "मां" भी है। मदर ऑफ ऑल डीलस! सवाल इतना-सा है कि विकसित होते देश की हवा जहरीली, पानी मृत्यु देने वाला, भोजन कैंसर कोशिकाएं बनाने वाला और दवाइयां मौत के और करीब ले जाने वाली (नक्ली) कैसे हो सकती हैं? क्या हमारे विकास मॉडल के केंद्र में इकोनॉमी तो होगी मगर इंसान न होगा? विकसित बन किसके लिए रहे हैं? दुनिया को दिखाने के लिए या अपनों को आगे ले जाने के लिए?

दुनिया को तो बुलंदी से बढ़ता भारत दिख ही रहा है। लेकिन दुनिया को यह भी दिख रहा है कि भारत में निवेश करने जाएंगे तो दिल्ली में लैंड करते ही फेफड़े लड़खड़ाए लगेगे, सांस उखड़ने लगेगी। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट बताती है कि भारत में हर साल 17 लाख लोगों की मौत प्रदूषण से होती है।

क्या सरकार ने तय किया है कि हम किस तरह के विकसित देश बनना चाहते हैं? अमेरिका जैसे, जो इंसान छोड़ इकोनॉमी को केंद्र में मान चुका है? सुनते थे कि अमेरिका में एक भी असामान्य मौत हो जाए तो वह जमीन-आसमान एक कर देता है। लेकिन मिनियोपोलिस में एक व्यक्ति को फेडरल एजेंटों ने ही गोली मार दी, महिला को गाड़ी में शूट कर दिया।

ट्रम्प सुरक्षा बल के पक्ष में ही खड़े हो गए जबकि पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। दुनिया पर मनमानी करते आए इस देश में 2021 के बाद से आम आदमी का जीवन-स्तर और क्रय-शक्ति गिरते चले गए। एक तिहाई मध्यमवर्गीय परिवार भोजन और स्वास्थ्य की बुनियादी जरूरतें

पूरी नहीं कर पा रहे हैं।

दूसरी तरफ, कहीं कम जीडीपी वाले विकसित देशों ने विकास की अपनी परिभाषा गढ़ी है। स्कैंडिनेवियाई देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इनका मंत्र है- बचपन से बुढ़ापे तक सुरक्षा। फिनलैंड में शिक्षा मुफ्त है, निजी स्कूल न के बराबर।

नॉर्वे अपनी प्राकृतिक संपदा का उपयोग नागरिकों के लिए वेलफेयर फंड बनाने में करता है। वहां स्वास्थ्य सेवाएं लगभग मुफ्त हैं। जापान ने लंबी उम्र और स्वास्थ्य सेवाओं को अपना मुख्य आधार बनाया है। यहां सड़कें सुरक्षित हैं, आपदा प्रबंधन गजब का है और ट्रेनें मिनटों की सटीकता से चलती हैं। प्रसिद्ध कोलंबियाई अर्थशास्त्री गुस्तावो पेट्रो ने कहा था- एक विकसित देश वह नहीं है जहां गरीबों के पास कारें हों, बल्कि वह है जहां अमीर सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हों।

इधर, हमारे देश में 2047 तक आधी आबादी शहरों में रह रही होगी। उन शहरों में जहां ट्रैफिक बेकाबू हो चुका है, हवा-पानी जहरीले हैं, 90 डिग्री के फ्लार्डओवर बन रहे हैं, गिर रहे हैं। स्थानीय निकाय और एजेंसियां गैर-जिम्मेदार हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट में मंत्री-अफसर का कमीशन और ठेकेदार का मुनाफा बढ़ता जा रहा है। एक विकासशील देश में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं? वह अपनी नीतियों से किस तरह की संस्कृति बना रही है?

नोबेल विजेता जोसेफ स्टिग्लिट्ज कहते थे- विकास का मतलब जीवन को बदलना है, सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं। अगर जीडीपी बढ़ रही है और लोगों का स्वास्थ्य व खुशहाली नहीं, तो वह विकास एक धोखा है। भावनात्मक मुद्दे चुनाव जिता सकते हैं लेकिन विकास के ब्लू प्रिंट में उस मतदाता की परवाह तो कीजिए जो आपको जिताएगा। अगर जीडीपी बढ़ रही है और लोगों का स्वास्थ्य व खुशहाली नहीं, तो वह विकास एक धोखा है।

विचार-मंथन - दुनिया पर विचार और भगवान पर विश्वास करें



इस समय एक बड़ा भ्रम चल रहा है, वो ये कि हम दुनिया पर विश्वास करते हैं और भगवान पर विचार करते हैं। आज जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, खासतौर पर विज्ञान और तकनीक के मामले में- उस पर हम आंख मूंदकर विश्वास कर रहे हैं। और भगवान है कि नहीं है, कृपा करता भी है या नहीं, इस पर बहुत विचार करते हैं।

दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी ही खोज के खतरों के लिए कहते हैं कि विज्ञान जिम्मेदार हाथों में सुरक्षित रहेगा, अन्यथा नुकसान पहुंचाएगा। पर जिम्मेदार कौन है? जिसको देखो वही दुरुपयोग करने में लगा है। आजकल तो परिवार के विचार को भी लोग अपनी व्यक्तिगत खुशी में रोड़ा मानते हैं।

पहले परिवार में रहने का मतलब था स्थायी रिश्ते और स्थायी जिम्मेदारी, अब चारों तरफ गैर-जिम्मेदारी का वातावरण बन गया है। घर के बाहर सरकारों ने दान दे-देकर गैर-जिम्मेदारों की फौज खड़ी कर दी और घर के भीतर संस्कारों के अभाव में सदस्य गैर-जिम्मेदार हो गए। और दोनों का मजा विज्ञान और तकनीक ले रहे हैं।



सुशील भोले

कोंदा-भैरा के गोठ

-सत्ता के परिवर्तन के संग कतकों जगा अउ संस्थान मन के नाँव मनला बलदे के जेन राजनीतिक चरित्तर चलत रहित्थे, ते सब के बीच म अभी खैरागढ़ के विश्व प्रसिद्ध संगीत विश्वविद्यालय के नाँव ल 'राजकुमारी इंदिरा सिंह कला संगीत विश्वविद्यालय' करे के घोषणा होइस हे, ते ह मोला गजब निक लागीस जी भैरा.

-सिरतोन आय जी कोंदा.. कतकों लोगन ल भोरहा होवय के ए ह कोन इंदिरा आय जेकर नाँव म विश्वविद्यालय के नाँव ल रखे हावय.

-हव भई.. अब तुरते समझ म आ जही के ए ह कोनो राजनीति ले जुड़े मनखे या उँकर संरक्षक के नहीं, भलुक खैरागढ़ रियासत के राजकुमारी इंदिरा सिंह के नाँव आय, जेकर सुरता म उहाँ के राजा ह ए ठउर ल दिए रिहिन हैं.

-सही आय.. राज्यपाल रमेन डेका ह अभी उहाँ संपन्न होय 17 वॉ दीक्षांत समारोह म इंदिरा नाँव ल पूरा फोरिया के लिखे के जेन घोषणा करे हे वो ह वाजिब म ऐतिहासिक हे.. एकर परघनी करे जाना चाही.

गलवान संघर्ष के बाद चीन ने किया था न्यूक्लियर टेस्ट



को चीन की तरफ से किए न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी है. चीनी सेना ने न्यूक्लियर विस्फोट को छिपाने की कोशिश की क्योंकि उन्हें पता था कि ये परीक्षण प्रतिबंधित गतिविधियों के प्रति प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करते हैं. डिनानो ने कहा है कि अमेरिका के न्यूक्लियर हथियार न्यूक्लियर संधि की सीमा के अधीन रहे. वहीं, रूस के बहुत बड़े भंडार का केवल छोटा सा हिस्सा प्रतिबंधित किया गया था. साथ ही न्यू स्टार्ट संधि में चीन का एक भी न्यूक्लियर हथियार कवर नहीं किया गया था. उन्होंने अमेरिका की लंबे समय से चली आ रही मांग रणनीतिक स्थिरता और हथियार नियंत्रण व्यवस्था को दोहराया.

अमेरिका के दावे पर क्या बोला चीन?

यूएस की ओर से किए गए दावे पर चीन की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है. चीन ने अमेरिका की तरफ से लगाए गए आरोपों का सीधा जवाब नहीं दिया है. चीन के राजदूत शन जियान ने कहा कि चीन ने ध्यान दिया है कि अमेरिका अपने बयान में तथाकथित चीन परमाणु खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है. चीन ऐसे झूठे आरोपों का कड़ा विरोध करता है. अमेरिका हथियारों को बढ़ाने की होड़ में सबसे बड़ा दोषी है. डिनानो ने कहा था कि चीन के पास 2030 तक एक हजार से ज्यादा परमाणु हथियार होंगे तो उस पर शन जियान ने कहा कि उनका देश अमेरिका और रूस की इस नई बातचीत में हिस्सा नहीं लेगा. हमारे पास हथियारों की संख्या का छोटा सा हिस्सा है. लगभग 600 के आसपास जबकि रूस और अमेरिका के पास लगभग 4 हजार हैं.

नई दिल्ली। अमेरिका ने चीन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने गलवान संघर्ष के कुछ ही दिनों बाद एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था. यूएस की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है. अब इसको लेकर चीन का भी रिएक्शन आया है. अमेरिका ने बताया कि 22 जून 2020 को चीन ने एक सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था. यह घटना गलवान घाटी में हुई जानलेवा झड़प के कुछ दिनों बाद की है, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी.

चीन ने न्यूक्लियर टेस्टिंग छिपाने की कोशिश की: अमेरिका

अमेरिका ने चीन पर न्यूक्लियर टेस्टिंग को लेकर ये आरोप जिनैवा के डिसआर्मेड कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं. यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर आर्म्स कंट्रोल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी थॉमस डिनानो ने कहा कि मैं यह बता सकता हूँ कि अमेरिका



फिर खुली पाकिस्तान की पोल, इस्लामाबाद आत्मघाती हमले का सामने आया सच!

नई दिल्ली। पाकिस्तान की राजधानी में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती बम धमाके में पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है. पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में एक अफगान नागरिक भी शामिल है, जिसे उन्होंने सुसाइड अटैक का मास्टरमाइंड बताया. नकवी के बयान के बाद पाकिस्तान की ओर से भारत को बदनाम करने की साजिश की फिर पोल खुली है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मोहसिन नकवी ने बताया कि संदिग्धों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए सर्च ऑपरेशन में एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी की भी मौत हो गई और तीन अन्य लोग घायल हुए हैं. नकवी का यह बयान तब आया जब इस्लामिक स्टेट ग्रुप की ओर से तारलाई इलाके की शिया मस्जिद में शुक्रवार की नमाज के दौरान हुए बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली गई.

इस आतंकी संगठन ने ली जिम्मेदारी

आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट खोरासान (ISKP) ने प्रोपेगंडा चैनल अमाक एजेंसी की ओर से बयान जारी किया और बताया कि इस आत्मघाती हमले को उसने ही करवाया था. ISKP के मुताबिक उसके खिलाफ जैनब्योन संगठन बनाकर लड़ रहे हैं. ISKP ने फ़िदायीन आत्मघाती हमलावर का चेहरा ब्लर करके तस्वीर भी जारी की है. ISKP के आधिकारिक प्रोपेगंडा चैनल अमाक एजेंसी की तरफ से जारी बयान में इस्लामिक स्टेट खोरासान ने बताया कि उसने कल शिया मस्जिद पर इसलिए आत्मघाती हमला करवाया था क्योंकि पाकिस्तानी शिया लड़ाके सीरिया में उसके खिलाफ जैनब्योन संगठन बनाकर लड़ रहे हैं।

'भले ही युद्ध थोप दिया जाए, न्यूक्लियर इनरिचमेंट नहीं छोड़ेंगे: ईरानी राष्ट्रपति



नई दिल्ली। ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन को कभी नहीं छोड़ेगा, भले ही देश पर युद्ध थोप दिया जाए. यह बयान ईरान के विदेश मंत्री ने रविवार को दिया है. तेहरान में एक फोरम पर बोलते हुए अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान ने अपने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम पर बहुत कीमत चुकाई है. उन्होंने कहा है कि हम संवर्धन पर इतना जोर क्यों देते हैं, अगर हम पर युद्ध थोप दिया जाए तो भी इसे छोड़ने से इनकार क्यों करते हैं? क्योंकि किसी को भी हमारे व्यवहार को तय करने का अधिकार नहीं है. दरअसल, ईरान के विदेश मंत्री ने यह बयान अमेरिकी दूत स्टीव विटकोंफ से मिलने के दो दिन बाद दिया है.



रूस में भारतीय छात्रों पर हमला कॉलेज के हॉस्टल में चाकूबाजी

नई दिल्ली। रूस के बश्कोर्तोस्तान गणराज्य के उफा शहर में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में चाकू से हमला होने की घटना सामने आई है. इस हमले में 4 भारतीय छात्रों समेत कई लोग घायल हो गए हैं. भारतीय दूतावास ने शनिवार (7 फरवरी 2026) की रात इस घटना की पुष्टि की है और बताया है कि सभी घायल छात्रों को इलाज मिल रहा है. भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए कहा कि उफा में एक दुर्भाग्यपूर्ण हमला हुआ है, जिसमें चार भारतीय छात्र भी घायल हुए हैं. दूतावास ने बताया कि वह रूस के स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है और कज़ान स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारी उफा खाना हो चुके हैं, ताकि घायल छात्रों को हर संभव मदद दी जा सके.

विदेश मंत्री बोले- यह तेहरान का अधिकार है

एक कार्यक्रम में बोलते हुए अराघची ने कहा था कि यूरेनियम इनरिचमेंट करना ईरान का अधिकार है. इसे जारी रहना चाहिए. साथ ही कहा है कि ईरान इस पर मुद्दे पर एक समझौते तक पहुंचने के लिए तैयार है. उन्होंने मस्कट में हुई बातचीत को अच्छी शुरुआत बताया है. साथ ही खुलासा किया कि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ हाथ मिलाने का मौका मिला है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि विश्वास बनाने के लिए फिलहाल लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा. बातचीत को जल्द ही फिर से शुरू करना पड़ेगा.

ट्रंप ने ईरान के साथ हुई चर्चा को अच्छा बताया

इधर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चर्चाओं को बहुत अच्छा बताया है. अगले सप्ताह एक और दौर का संकेत दिया है. साथ ही कहा है कि वाशिंगटन ने प्रेशर बनाए रखा है. ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने वाला एक नया कार्यकारी आदेश लागू हो गया है. ईरानी तेल निर्यात से जुड़ी शिपिंग संस्थाओं और जहाजों को निशाना बनाने वाले नए प्रतिबंध लगाए गए हैं।

PAK के F-16 अपग्रेड करना भारत के लिए खतरा

नई दिल्ली। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील का ऐलान हो चुका है. डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीद को लेकर भारत पर जुर्माना को लेकर लगाए गए 25 फीसदी टैरिफ को भी हटा लिया है. हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर भारत सीधे या किसी दूसरे चैनल के माध्यम से रूसी तेल खरीदता है तो यह जुर्माना फिर से लगा दिया जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये को एक्सपर्ट्स डबल स्टैंडर्ड करार दे रहे हैं.

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्लल ने इस घटनाक्रम को डोनाल्ड ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड बताया. उन्होंने कहा कि यह साफ तौर पर दबाव बनाने की कोशिश है क्योंकि रूस से हमारी तेल खरीद का अमेरिका के साथ किसी द्विपक्षीय ट्रेड डील से कोई संबंध नहीं है. यह एक राजनीतिक मुद्दा है, जिसका निपटारा राजनीतिक स्तर पर ही होना चाहिए, न कि टैरिफ के जरिए.



उन्होंने X पर पोस्ट कर कहा, 'रूस से भारत की तेल खरीद अमेरिका की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसके उलट अमेरिका की ओर से पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को अपग्रेड करना भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए खतरा जरूर पैदा करता है. वहीं, चीन जो रूस से काफी ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल और गैस इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन उसके प्रति अमेरिका का नरम रवैया भी भारत की सुरक्षा और विदेश नीति के लिए चिंता का विषय है, खासकर जब चीन का रुख भारत के प्रति हमेशा से दुश्मनी के तौर पर रहा है.'

मैक्रों के भारत दौरे पर 114 राफेल को लेकर हो सकती है डील

थर-थर कांपेगा पाकिस्तान! भारतीय वायुसेना की बढ़ेगी ताकत

नई दिल्ली। 18 से 20 फरवरी तक होने वाली AI समिट के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भारत आएंगे. इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) की फरवरी के दूसरे सप्ताह में बैठक होने वाली है. इस बैठक में रक्षा खरीद से संबंधित बड़े प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा. रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव अगले सप्ताह फ्रांस से 32 लाख करोड़ रुपये की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए स्वीकृति देने का है. प्रस्तावित परियोजना में उन 18 विमानों की खरीद शामिल होगी जो तुरंत उड़ान भरने की स्थिति में होंगे तो वहीं कुछ विमानों का भारत में निर्माण किया जाएगा. जिनमें 60 फीसदी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा.

फ्रांस से 114 राफेल विमानों को लेकर होगी डील

इस समझौते के तहत खरीदे जाने वाले 114 राफेल विमानों में से लगभग 80 फीसदी का निर्माण भारत में ही किया जाएगा. सूत्रों के अनुसार इस परियोजना के तहत भारतीय वायु सेना को 88 सिंगल सीटर और 26 दो-सीटर विमान मिलेंगे, जिनमें से अधिकांश का निर्माण



डसॉल्ट और भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनियों के सहयोग से भारत में किया जाएगा. रक्षा खरीद बोर्ड द्वारा पिछले महीने मंजूरी दी जा चुकी है. हाई लेवल पर एक और मंजूरी मिलने के बाद तकनीकी और वाणिज्यिक वार्ता की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी. इमैनुएल मैक्रों की भारत यात्रा के दौरान इस सौदे को अंतिम रूप दिया जा सकता है. भारतीय वायु सेना वर्तमान में लगभग 30 लड़ाकू स्क्वाड्रन संचालित कर रही है, जो इसकी स्वीकृत 42 स्क्वाड्रन की क्षमता से काफी कम है, ऐसे समय में

जब पाकिस्तान और चीन से खतरे की आशंकाएं बढ़ रही हैं.

पाकिस्तान-चीन गठबंधन ने बढ़ाई चिंता

रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ-साथ पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ते रणनीतिक गठबंधन ने क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया है. सौदा पूरा होने के बाद भारतीय वायु सेना के पास 150 राफेल विमानों का बेड़ा होगा, साथ ही भारतीय नौसेना के पास 26 विमान होंगे, जिनमें फ्रांसीसी विमानों का विमानवाहक पोत संस्करण शामिल होगा.

भारत-अमेरिका ट्रेड डील किसानों को नहीं होगा नुकसान: पीयूष गोयल

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पूरी जानकारी साझा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भारत और अमेरिका का नया व्यापार समझौता भारत के किसानों, डेयरी उत्पादकों या ग्रामीण रोजगारों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा टैरिफ ढांचा सुनिश्चित किया है,



जो देश के सबसे संवेदनशील खाद्य क्षेत्रों की रक्षा करता है। साथ ही, भारत के मैन्युफैक्चर, तकनीकी उत्पादकों और लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए निर्यात के व्यापक मौका खोलता है। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, वॉशिंगटन की ओर से कई भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ करीब 50 प्रतिशत से घटाकर एक समान 18 प्रतिशत करने के बाद भारत को कई प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

भारत ने इन क्षेत्रों को पूरी तरह सुरक्षित

भारत ने कई क्षेत्रों पर शून्य टैरिफ की रियायत दी है। टैरिफ पहले की तरह ही रखा जाएगा। यह सरकार के राजनीतिक मैसेज का मुख्य हिस्सा है।

(i) खाद्यान्न और जरूरी कृषि उत्पाद

भारत ने उन जरूरी खाद्य श्रेणियों को पूर्ण रूप से संरक्षण दिया है, जिन पर लाखों किसानों की आजीविका निर्भर है-

गेहूं, चावल, मक्का, सोया और तिलहन, पोल्ट्री और मांस की कई कैटेगोरियां, एथेनॉल, तंबाकू। इन सभी पर हाई टैरिफ पहले के जैसे ही रहेंगे और अमेरिकी निर्यातकों को कोई नया एक्सेस नहीं दिया जाएगा।

(ii) भारत का पूरा डेयरी सेक्टर

इस सेक्टर को 100 प्रतिशत सुरक्षित बताया गया है।

दूध (सभी रूपों में)
चीज, मक्खन, घी, क्रीम, दही,
बटरमिल्क, व्हे, पनीर,
सरकार ने कहा कि अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बाजार में कोई एक्सेस नहीं दिया गया है।

(iii) सब्जियां, फल और प्रोसेस्ड फूड

सरकार ने कहा कि ताजा, फ्रोजेन, ड्रायड और कैनड प्रोडक्ट्स की एक लंबी लिस्ट को पूरी तरह सुरक्षित रखा गया है।

ताजी सब्जियां : आलू, लहसुन, मशरूम, लौकी, भिंडी, हरी मिर्च, मटर, बीन्स, कद्दू और कई अन्य शामिल हैं।

प्रोसेस्ड सब्जियां : प्रोजेन आलू, मटर और बीन्स, मिक्स सब्जियां, डिब्बाबंद प्रोडक्ट्स, प्रिजर्व्ड खीरा और मशरूम।

सूखी सब्जियां और दालें : सूखा प्याज और लहसुन, डिहाइड्रेटेड पाउडर, हरे मटर, काबुली चना, बीन्स, शकरकंद।

संवेदनशील फल : केला और केले से बने प्रोडक्ट्स

आम और आम से बने प्रोडक्ट्स : साइट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, कागजी नींबू और ग्रेपफ्रूट, बेरी कैटेगरी के फल, जिनमें स्ट्रॉबेरी भी शामिल हैं।

(iv) मसाले और भारत की स्वाद विरासत

काली मिर्च, लौंग, मिर्च, दालचीनी, धनिया, जीरा, हल्दी, अजवाइन, मेथी, सरसों, कैसिया और अन्य संबंधित मसाला प्रोडक्ट्स।

(v) चाय

ब्लैक टी, ग्रीन टी और टी बैन्स भारत के प्रतिष्ठित चाय उद्योग की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से संरक्षित रहेंगे। सरकार के मुताबिक, कृषि, डेयरी, मसाले और चाय क्षेत्रों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

8वें वेतन आयोग की वेबसाइट लॉन्च वेतन बढ़ोतरी की उम्मीद हुई तेज



नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवें वेतन आयोग को लेकर राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय से वेतन बढ़ोतरी और ढांचे में बदलाव को लेकर चल रहा इंतजार अब खत्म होने की दिशा में आगे बढ़ता दिख रहा है। सरकार की ओर से 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग के लिए दिल्ली में ऑफिस की जगह सुनिश्चित की थी। जहां से आयोग अपने आगे का काम कर सकता है। वहीं, अब वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है। इस वेबसाइट के जरिए आयोग ने कर्मचारियों और अन्य स्टेकहोल्डर्स से संबंधित सुझाव मांगे हैं कि वे अपने वेतन ढांचे में किस तरह के सुधार और बदलाव चाहते हैं। आइए इस विषय में जानते हैं.....

8वें वेतन आयोग ने सभी को साथ जोड़ने के लिए यह कदम उठाया है। आयोग ने साफ किया है कि वह अब केवल मंत्रालयों, विभागों और कर्मचारी संगठनों से ही नहीं, बल्कि आम कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से भी सुझाव और विचार लेना चाहता है। इसी

उद्देश्य से 'MyGov' पोर्टल के साथ साझेदारी की गई है, ताकि हर व्यक्ति अपनी बात आसानी से आयोग तक पहुंचा सके। आयोग का मानना है कि जिन लोगों पर इसका सीधा असर पड़ता है, उनकी भागीदारी सबसे जरूरी है। चाहे आप नौकरी में हों, रिटायर हो चुके हों या किसी यूनियन से जुड़े हों, आप आधिकारिक वेबसाइट या MyGov पोर्टल के जरिए अपनी राय दर्ज करा सकते हैं।

सुझाव भेजने की प्रक्रिया हुई पूरी तरह ऑनलाइन

8वें वेतन आयोग ने साफ तौर पर बताया है कि अब सुझाव भेजने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल होगी। आयोग फिजिकल दस्तावेज, पत्र या ईमेल के जरिए भेजी गई किसी भी सुझाव पर विचार नहीं करेगा। सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को अपनी बात रखने के लिए केवल MyGov पोर्टल का ही इस्तेमाल करना होगा। आयोग ने यह भी भरोसा दिलाया है कि सुझाव देने वाले लोगों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

अल्फाबेट का रेवेन्यू पहली बार 400 बिलियन डॉलर के पार

नई दिल्ली। दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियों में शामिल गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट ने साल 2025 में पहली बार 400 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू का आंकड़ा पार कर लिया है। चौथी तिमाही के नतीजों के बाद गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साल की आखिरी तिमाही को बेहद शानदार बताया। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय एआई इकोसिस्टम के चलते सर्च और क्लाउड सर्विसेज में आई तेज बढ़ोतरी को दिया है। जिससे कंपनी की कमाई में इतनी बड़ी उछाल देखने को मिली है। अल्फाबेट की चौथी तिमाही के नतीजों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। कंपनी ने अक्टूबर दिसंबर की तिमाही में 34.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 30 फीसदी की तेजी दर्ज की है। साथ ही इस दौरान कंपनी का कुल रेवेन्यू 18 प्रतिशत से बढ़ा है। जिसके कारण पहली बार कंपनी का रेवेन्यू 400 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है।

एक फोन कॉल ने किस्मत बदल दी: सिराज

नई दिल्ली। मोहम्मद सिराज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले मैच में 3 विकेट लिए। टूर्नामेंट से 24 घंटे पहले ही उन्हें स्क्वॉड में शामिल किया गया था, क्योंकि हर्षित राणा चोट के कारण बाहर हो गए थे। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए सिराज ने कहा कि उन्हें पता था कि वह वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। लेकिन ऊपर वाले ने पूरी तकदीर बदल दी। उन्होंने बताया कि सूर्यकुमार यादव ने उन्हें फोन करके जब इसके बारे में बताया तो उन्होंने इसे मजाक समझा।



मोहम्मद सिराज ने कहा, "24 घंटे पहले ही मुझे पता चला और मैं प्लाइंट में बैठा था तब भी मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे ये कोई सपना हो, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि वर्ल्ड कप में खेलूंगा। एक साल से प्लानिंग चल रही थी, मैं टी20 नहीं खेल रहा था तो समझ आ गया था कि मैं इस वर्ल्ड कप में तो नहीं खेलूंगा। लेकिन ऊपर

वाले ने पूरी तकदीर बदल दी। 24 घंटे पहले मैं अपने परिवार के साथ था। मुझे मैसेज आया कि 'आपका आगे क्या प्लान है?' तो मैंने कहा मुझे तंग मत करो, मैं आराम कर रहा हूँ, तभी मुझे सूर्यकुमार यादव का फोन आया."

सिराज ने समझा सूर्यकुमार की बात को मजाक

मोहम्मद सिराज ने कहा, "मुझे सूर्यकुमार यादव का फोन आया और उन्होंने कहा कि 'मिया तैयार हो जा और बैंग पैक करके आ जा' मैंने कहा कि सूर्या भाई मजाक मत करो क्योंकि ये तो होने वाला नहीं है। फिर उन्होंने कहा 'मिया मैं सच बोल रहा हूँ, आज।' तो मेरे लिए ये शॉकिंग खबर थी। ऊपर वाले ने जो लिख दिया तो उसे कोई नहीं बदल सकता। मैं टीम में न सिर्फ आया बल्कि मैच भी खेल लिया। गॉड ग्रेट है।

वरना नेपाल ने कर दिया था उलटफेर, 2026 टी20 वर्ल्ड कप का सबसे 'श्रिलिंग' मैच

सैम कर्न ने बचाई इंग्लैंड की लाज, 4 रन से जीता मैच

नई दिल्ली। रविवार का दिन भला क्रिकेट फैंस के लिए इससे रोमांचक नहीं हो सकता था। नेपाल एक एसोसिएट टीम है, लेकिन उसने काम किसी टॉप रैंकिंग वाली टीम जैसा करके दिखाया है। वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रन बनाए थे। नेपाल की टीम लक्ष्य से सिर्फ 4 रन दूर रह गई। इंग्लैंड ने चाहे मैच जीत हो, लेकिन नेपाल ने दुनियाभर के क्रिकेट फैंस का दिल जीत है। वो सिर्फ 6 गेंद थीं, जिन्होंने नेपाल के हाथों से जीत छीन ली। आज नेपाल बहुत बड़ा उलटफेर कर ही चुका था, लेकिन सैम कर्न के ओवर ने इंग्लैंड की लाज बचाने का काम किया। इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 184 रनों का स्कोर खड़ा किया था। हैरी ब्रूक और जैकब बैथेल ने पचासा ठोका, वहीं विल जैक्स ने भी तूफानी पारी खेली थी।

6 गेंद, बच गई इंग्लैंड की लाज

185 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने आई नेपाल की टीम ने 19 ओवरों में 175 रन बना लिए थे। दीपेन्द्र सिंह एरी 44 रन और कप्तान रोहित पॉडेल ने 39 रनों का योगदान देकर इंग्लैंड की टीम को बैकफुट पर भेज दिया था। आलम यह था कि नेपाल को आखिरी 6 गेंद में 10 रन बनाने थे। लोकेश बाम जिस तरह की बैटिंग कर रहे थे, उससे इंग्लैंड की हार तय लग रही थी। मगर सामने थे अनुभवी सैम कर्न, जिनके पास अनुभव के साथ-साथ जबरदस्त गेंदबाजी वेरिएशन भी है। सैम कर्न ने अंतिम ओवर में केवल 5 रन दिए और इंग्लैंड को बहुत बड़े उलटफेर का शिकार बनने से बचाया। आपको याद दिला दें कि टी20



वर्ल्ड कप 2026 के पहले दिन नीदरलैंड्स के हाथों पाकिस्तान भी बड़े उलटफेर का शिकार बनने से बचा था।

रिलायंस समेत 8 कंपनियों के मार्केट कैप में 4.55 लाख करोड़ की बढ़त

नई दिल्ली। बीते सप्ताह शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। मजबूती का सीधा फायदा देश की बड़ी कंपनियों को मिला। टॉप 10 में शामिल 8 कंपनियों के मार्केट कैप में करीब 4.55 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इस बढ़त में सबसे आगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का नाम रहा। जिसने बाकी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। सप्ताह के दौरान प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बीएसई सेसेक्स 2,857.46 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। बाजार के इस पॉजिटिव रुख की वजह से निवेशकों को तगड़ी कमाई का मौका मिला। जिससे उनकी कुल संपत्ति में इजाफा हुआ है। शेयर बाजार की तेजी का असर देश की बड़ी कंपनियों पर भी साफ नजर आया। टॉप-10 में शामिल रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बजाज फाइनेंस, एलआईसी और हिंदुस्तान यूनिलिवर के बाजार मूल्य में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। इन कंपनियों के शेयरों में आई मजबूती से निवेशकों का भरोसा भी मजबूत हुआ। इस तेजी का सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज को मिला। कंपनी के मार्केट कैप में करीब 1.42 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। जिससे इसका कुल मार्केट कैप बढ़कर लगभग 19.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह कंपनी की मजबूत स्थिति को दिखाता है।

नई दिल्ली। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026 की आखिरी बैठक में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया। छह सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा। इसका सीधा असर होम लोन पर पड़ता है, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने से ईएमआई भी यथावत रहेंगी। इससे उन लोगों को खास राहत मिली है जो घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या अंतिम चरण में फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपने वित्तीय निर्णय अधिक भरोसे के साथ लेने का मौका मिलेगा।

रेपो रेट 5 में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की तीन दिवसीय बैठक के बाद शुक्रवार को वित्त वर्ष 2026 की आखिरी बैठक में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का फैसला किया गया। छह सदस्यीय समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25 प्रतिशत पर स्थिर रखा। इसका सीधा असर होम लोन पर पड़ता है, क्योंकि ब्याज दरों में कोई बदलाव न होने से ईएमआई भी यथावत रहेंगी। इससे उन लोगों को खास राहत मिली है जो घर खरीदने की योजना बना रहे हैं या अंतिम चरण में फैसला लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपने वित्तीय निर्णय अधिक भरोसे के साथ लेने का मौका मिलेगा।

पवन साय बंगाल में बना रहे हैं जीत की रणनीति

56 विधानसभाओं की मिली है जिम्मेदारी, सीटों की स्थिति के बारे में ले रहे पूरी जानकारी

रायपुर। भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय को बंगाल चुनाव के लिए 56 विधानसभाओं के एक जोन की जिम्मेदारी दी गई है। वे वहां का लगातार दौरा कर रहे हैं। पहले वहां पर एक माह तक रुक कर उन्होंने 35 विधानसभाओं की स्थिति के बारे में पूरी जानकारी लेकर वहां के लिए जीत की रणनीति तैयार की है।

अब फिर से बंगाल जाकर वहां पर डटे हैं और बची विधानसभाओं के लिए भी वे रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। बंगाल में अलग अलग जोन बनाकर करीब आधा दर्जन राज्यों के संगठन महामंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। बिहार चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय संगठन का बड़ा फोकस बंगाल चुनाव पर है। इस साल मार्च-अप्रैल में वहां पर चुनाव संभावित है। भाजपा ने बीते साल से ही इसको लेकर तैयारी प्रारंभ कर दी है। वैसे भी भाजपा

हमेशा से किसी भी राज्य में चुनाव से काफी पहले तैयारी प्रारंभ कर देती है। बिहार चुनाव में भी भाजपा ने काफी पहले से तैयारी की थी। प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल को वहां पर 50 विधानसभाओं की



जिम्मेदारी दी गई थी। श्री जामवाल बिहार में चार माह तक रहे और अपनी जिम्मेदारी वाली विधानसभाओं में लगातार बैठकें लेकर रणनीति बनाने का काम किया। इसका परिणाम यह रहा कि 50 सीटों में से 25 सीटों में भाजपा के प्रत्याशी मैदान में उतारे गए तो इसमें से 23 सीटों में भाजपा के प्रत्याशियों को जीत मिली।

जानकारी लेकर बना रहे रणनीति

भाजपा का राष्ट्रीय संगठन लगातार प्रदेश के



नेताओं पर भरोसा कर रहा है। बिहार चुनाव में प्रदेश के जिन भी नेताओं को वहां पर विधानसभाओं की जिम्मेदारी दी गई थी, उन सभी में भाजपा के प्रत्याशी जीते। अब राष्ट्रीय संगठन प्रदेश के नेताओं को बंगाल की भी जिम्मेदारी देगा।

पहले चरण में प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय को वहां पर एक जोन की 56 विधानसभाओं का जिम्मा देकर बीते साल से रणनीति बनाने का काम दिया गया है। श्री साय लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने वहां

पर एक माह से ज्यादा समय तक रहकर 35 विधानसभाओं में बैठक करके उनके बारे में पूरी जानकारी ली है।

इसी के साथ वहां पर कैसे भाजपा को जीत मिल सकती है, इसको लेकर रणनीति भी बनाई गई है। इस रणनीति के हिसाब से इन विधानसभाओं में काम भी प्रारंभ कर दिया गया है। इसके बाद वे फिर से अब बंगाल के दौरे पर हैं और बची विधानसभाओं के लिए भी रणनीति बना रहे हैं। वे वहां पर चुनाव तक लगातार डटे रहेंगे।



कांफेरिट परस्त भाजपा सरकार पूंजीपति मित्रों को संसाधन लुटा रही

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर कांफेरिट परस्ती के आरोप लगाए। पीसीसी प्रवक्ता सुरेन्द्र वर्मा ने दावे किए कि भाजपा सरकारों का फोकस केवल संसाधनों की लूट पर है। जंगल और खनिज संसाधन समेत नदियों पर भी भाजपा सरकार के पूंजीपति मित्रों की बुरी नजर लग गई है। बस्तर के नदी, नालों के पानी के सहारे करोड़ों टन लौह अयस्क ले जाया जा रहा है। किरन्दुल स्थित एनएमडीसी खदानों से रोजाना औसतन 20 हजार टन लौह अयस्क चूर्ण स्लरी पाइप लाइन के जरिए अपने विशाखापट्टनम स्थित निजी स्टील प्लांट ले जाया जा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक बस्तर की शबरी नदी और दंतेवाड़ा के मदाड़ी नाले के हजारों क्यूसेक पानी का उपयोग रोजाना इस परिवहन में किया जा रहा है।

सहयोग केन्द्र में आगामी सप्ताह पांच कैबिनेट मंत्री सुनेंगे समस्याएं



रायपुर। भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कैबिनेट मंत्रियों की मौजूदगी 9 से 13 फरवरी तक जारी रहेगी। इस दौरान सहयोग केन्द्र में हर दिन अलग-अलग विभागों के मंत्री उपस्थित होकर कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। वहीं उनकी समस्याओं का भी निराकरण किया जाएगा। भाजपा संगठन ने 13 फरवरी तक के लिए मंत्रियों की उपस्थिति का कार्यक्रम तय कर दिया है।

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सहयोग केन्द्र में 9 फरवरी को कृषि मंत्री रामविचार नेताम मौजूद रहेंगे। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्राही भी रहेंगे। वहीं 10 फरवरी को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव कार्यकर्ताओं और आम लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उनके साथ सहयोग के लिए

प्रदेश उपाध्यक्ष जी. वेंकटेश्वर राव की उपस्थिति रहेगी। गारतीय जनता पार्टी कार्यालय छत्तीसगढ़ फरवरी को कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत सहयोग केन्द्र में उपस्थिति देंगे। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रबल प्रताप सिंह जूदेव मौजूद रहेंगे।

जबकि 12 फरवरी को वित्त मंत्री ओपी चौधरी सहयोग केन्द्र में समस्याएं सुनेंगे। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन सहयोग के तौर पर मौजूद रहेंगे। इधर 13 फरवरी को वन मंत्री केदार कश्यप अपनी उपस्थिति देंगे। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष रामजी भारती को संबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि भाजपा दफ्तर के सहयोग केन्द्र में पहले अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भी समस्याएं सुनी हैं। वहीं आवेदनों का निराकरण करने के दावे भी किए हैं।

खरगे व राहुल देंगे छत्तीसगढ़ के जिला कांग्रेस अध्यक्षों को संगठनात्मक टिप्स

रायपुर। संगठन सृजन के तहत नियुक्त छत्तीसगढ़ के शहर एवं जिला कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एवं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संगठनात्मक टिप्स देंगे। जिला अध्यक्षों का पहला प्रशिक्षण 10 फरवरी को दिल्ली में होगा। हालांकि इस दौरान 8 राज्यों के जिला अध्यक्षों को संयुक्त तौर पर बुलाया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ के सभी जिला अध्यक्ष शामिल हैं। अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत होने वाले इस प्रशिक्षण में जिला स्तर पर संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ सत्ताधारी दल के जनविरोधी और राजनीतिक मुद्दों पर संघर्ष को लेकर भी रणनीतिक एक्सरसाइज होगी। इसके बाद राज्य में दूसरे दौर का प्रशिक्षण कार्यक्रम तय किया जाएगा।

संगठन सृजन के तहत नियुक्तियों के बाद अब तक प्रदेश के शहर एवं जिला कांग्रेस अध्यक्षों का प्रशिक्षण नहीं हो पाया है। यही वजह है कि अभी भी संगठनात्मक गतिविधियां सिर्फ औपचारिक कार्यक्रमों तक ही सिमटी हुई हैं। एआईसीसी ने 8 राज्यों के जिला अध्यक्षों का एक साथ पहला अभिमुखीकरण कार्यक्रम तय कर दिया है। इंदिरा भवन दिल्ली



में 10 फरवरी को इस प्रशिक्षण में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिला अध्यक्षों से सीधे संवाद करेंगे। इस दौरान संगठन को कामकाज और राजनीतिक मसलों पर आक्रामकता से काम करने विशेष तौर पर टिप्स भी दिए जाएंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर का प्रशिक्षण सत्र आयोजित कराने की तैयारी है। माना जा रहा है कि मार्च माह में जिला अध्यक्षों समेत ब्लॉक अध्यक्षों और एआईसीसी से जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण तय कर दिया गया है, लेकिन अब तक किसी भी स्तर पर कार्यकारिणी ही घोषित नहीं हो पाई है। प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी तो दो साल से ज्यादा समय से अटकी पड़ी है।

भूपेश-साव को दी गई अहम जिम्मेदारी

असम चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं पर दांव

रायपुर। अप्रैल में होने वाले असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल को सीनियर आब्जर्वर बनाया है।

वहीं भाजपा ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव को यहां की 9 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी है। चाय बगानों में काम करने वाले छत्तीसगढ़ मूल के मतदाताओं पर दोनों पार्टियों का फोकस रहेगा। ये मतदाता असम चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाजपा आलाकमान ने असम की जिन 9 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी अरुण साव को दी है, वहां चाय बगानों में काम करने वाले छत्तीसगढ़ मूल के मतदाताओं पर फोकस छत्तीसगढ़ मूल के मतदाता प्रभावी माने जाते हैं। श्री साव जल्द ही इन इन क्षेत्रों का दौरा कर विधानसभावार सांगठनिक बैठकें करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय मजबूत करेंगे। ओबीसी वर्ग के बड़े चेहरे और रणनीतिकार माने जाने वाले अरुण साव का असम प्रवास चुनाव संपन्न होने तक लगातार बना रहेगा।



उनका फोकस प्रशासनिक पकड़ के साथ-साथ संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर रहेगा। भाजपा का मानना है कि छत्तीसगढ़ी श्रमिकों और प्रवासी मतदाताओं से सीधा संवाद पार्टी को निर्णायक बढ़त दिला सकता है।

असम दौरा कर जमीनी फीडबैक ले चुके हैं भूपेश

कांग्रेस ने भी असम चुनाव में छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा जताया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को पार्टी ने सीनियर आब्जर्वर नियुक्त किया है और वे पहले ही असम दौरे कर जमीनी फीडबैक ले चुके हैं। उनके साथ विकास उपाध्यक्ष को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है, जो पिछले पांच सालों से असम कांग्रेस के प्रभारी सचिव हैं। उन्हें इस बार 50 विधानसभा सीटों का प्रभार सौंपा गया है। कांग्रेस ने इसके अलावा चार से पांच अन्य नेताओं को भी पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। पार्टी हाईकमान को उम्मीद है कि अनुभवी नेताओं की टीम चुनावी रणनीति को मजबूती देगी।

चुनाव आयोग सुनिश्चित करे कि फार्म-7 का दुरुपयोग न हो : बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, भाजपा एसआईआर प्रक्रिया को प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाकर गड़बड़यां कर रही है। वर्तमान में चल रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के अंतर्गत मतदाता नाम विलोपन के लिए आवेदन फार्म-7 का कई जिलों में दुरुपयोग किया जा रहा है। यह अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि इससे पात्र एवं वास्तविक मतदाताओं के नाम बिना जानकारी, सहमति के मतदाता सूची से हटाए जाने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा, प्रदेश की भाजपा द्वारा बड़ी संख्या में फार्म-7 का प्रिंट करवाकर आपत्ति करवाई जा रही है। आपत्ति अनाधिकृत लोगों द्वारा की जा रही है और अनाधिकृत अधिकारी को आपत्ति दी जा रही है, जो कानून का खुला उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी, सरकार की शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। अधिकतर में शिकायतकर्ता का अस्तित्व ही नहीं है। जहां शिकायतकर्ता का अस्तित्व है, वहां पर शिकायत झूठी है।



बस्तर आकर ऐसा लग रहा जैसे में अपने घर आई हूं: राष्ट्रपति

आदिवासियों की संस्कृति में बसती है छत्तीसगढ़ की आत्मा



रायपुर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु आज सुबह बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर पहुँचीं, जहाँ उन्होंने संभाग स्तरीय बस्तर पंडुम-2026 का शुभारंभ किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने इस अवसर पर कहा कि आदिवासियों की संस्कृति में छत्तीसगढ़ की आत्मा बसती है। उन्होंने बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी के जयघोष के साथ अपने उद्बोधन की शुरुआत की। राष्ट्रपति ने कहा कि देश में छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है, जहाँ सरकार अपनी संस्कृति, जनजातीय परंपराओं और प्राचीन विरासतों को संरक्षित करने के लिए बस्तर पंडुम जैसे आयोजन कर रही है। यह आयोजन आदिवासियों की गौरवशाली संस्कृति का जीवंत प्रतिबिंब है।

जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित इस शुभारंभ समारोह में बड़ी संख्या में आदिवासी कलाकार और विशाल जनसमूह मौजूद रहा। सभी को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रदेश की विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रही है। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जनजातीय उत्थान के लिए निरंतर बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजातीय गौरव उत्कर्ष अभियान तथा नियद नेल्ला नार जैसी योजनाओं के जरिए जनजातीय समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है। राष्ट्रपति ने बस्तर क्षेत्र में आदिवासी बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष जोर देते हुए कहा

कि जनजातीय बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए शासन के साथ-साथ समाज और उनके माता-पिता को भी आगे आना होगा। उन्होंने बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और गौरवशाली परंपराओं की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में प्राचीन परंपराओं की जड़ें आज भी मजबूत हैं। बस्तर पंडुम जनजातीय समुदाय की पहचान, गौरव और समृद्ध परंपराओं को प्रोत्साहित करने वाला एक महत्वपूर्ण मंच है। राष्ट्रपति ने बताया कि बस्तर पंडुम में 54 हजार से अधिक आदिवासी कलाकारों ने पंजीयन कराया है, जो अपनी सांस्कृतिक जड़ों से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि हिंसा का मार्ग छोड़कर माओवादी मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था बढ़ रही है। वर्षों से बंद विद्यालय पुनः खुल रहे हैं, दुर्गम वनांचल क्षेत्रों में सड़कें और पुल-पुलियों का निर्माण हो रहा है तथा ग्रामीणजन विकास से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बस्तर की सुंदरता और संस्कृति सदैव लोगों के आकर्षण का केंद्र रही है, किंतु दुर्भाग्यवश चार दशकों तक यह क्षेत्र माओवाद से ग्रस्त रहा, जिससे यहां के निवासियों को अनेक कष्ट झेलने पड़े। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने कहा कि भारत सरकार की माओवादी आतंक के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई के परिणामस्वरूप वर्षों से व्याप्त भय, असुरक्षा और अविश्वास का वातावरण अब समाप्त हो रहा है। माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं और नागरिकों

51 माओवादी कैडरों का आत्मसमर्पण, शांति की दिशा में बड़ा कदम - साय



रायपुर। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में शांति, विश्वास और विकास की दिशा में एक और महत्वपूर्ण सफलता सामने आई है। जिला बीजापुर में 30 और सुकमा में 21 माओवादी कैडरों ने राज्य सरकार की पुनर्वास आधारित पहल "पूना मारगेम: पुनर्वास से पुनर्जीवन" के अंतर्गत आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया। आत्मसमर्पण करने वाले इन कैडरों पर कुल 1.61 करोड़ का इनाम घोषित था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हथियारों का परित्याग कर संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में आस्था व्यक्त करना यह स्पष्ट संकेत देता है कि सुरक्षा, सुशासन और समावेशी प्रगति ही किसी भी क्षेत्र के दीर्घकालिक भविष्य की सुदृढ़ नींव होते हैं। यह घटनाक्रम बस्तर में शांति स्थापना के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों का सकारात्मक और ठोस परिणाम है। बीते दो वर्षों में बस्तर के दूरस्थ एवं संवेदनशील क्षेत्रों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार और बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया गया है। इस विकासक्रम पहल ने भटके युवाओं को हिंसा का रास्ता छोड़कर लोकतांत्रिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि सरकार की सुशासन आधारित नीति का केंद्र बिंदु सुरक्षा के साथ-साथ विश्वास, पुनर्वास और भविष्य की संभावनाओं का निर्माण है। आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी विजन, माननीय अमित शाह के दृढ़ संकल्प तथा राज्य सरकार के सतत प्रयासों से बस्तर आज भय और हिंसा से निकलकर विश्वास, विकास और नए अवसरों की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में बस्तर एक विकसित, शांत और समृद्ध क्षेत्र के रूप में देश के सामने नई पहचान स्थापित करेगा।

छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास के मोर्चों पर की उल्लेखनीय प्रगति

गृह मंत्री अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक ली

मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा



रायपुर। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। साथ ही, गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ में विभिन्न विकास कार्यों पर भी एक समीक्षा बैठक की। इन बैठकों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, उप-मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा, केन्द्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो (IB) के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के महानिदेशक तथा छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड, ओडिशा और महाराष्ट्र के गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक उपस्थित थे।

बैठक को संबोधित करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि केन्द्र और छत्तीसगढ़ सरकार की सुरक्षा केन्द्रित रणनीति (Security Centric Strategy), इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार व आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि आगामी 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हो रहा है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ कभी नक्सली हिंसा का गढ़ था, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के

नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकार में यह अब विकास का पर्याय बन चुका है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के युवा खेल, फॉरेंसिक और तकनीकी शिक्षा को गति देते हुए अपनी संस्कृति व परंपराओं को भी सहेज रहे हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में नक्सलवाद अंत के कगार पर पहुँच चुका है और 31 मार्च 2026 से पहले देश पूरी तरह नक्सल-मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि कई पीढ़ियों को गरीबी और अशिक्षा के अंधकार में धकेलने वाले नक्सलवाद से देश जल्द ही निजात पाने वाला है। श्री शाह ने कहा कि माओवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई बिखरी हुई (scattered) नहीं होनी चाहिए। विभिन्न राज्यों और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच सुचारु समन्वय की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शेष बचे माओवादियों को अन्य राज्यों में भागने नहीं दिया जाना चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को विकास के समान अवसर प्राप्त हों।

बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज'

रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां

बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बार फिर दहशत का माहौल है। मुंबई में मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई। इस घटना ने आम लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सितारे कितने सुरक्षित हैं। रोहित शेट्टी से पहले भी कई बड़े नाम ऐसे हैं, जिनके घर या ऑफिस को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं में कुछ मामलों ने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था।



सिद्धू मूसेवाला

पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब के मानसा जिले में दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेरकर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री, बल्कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया।



कपिल शर्मा

कमीडियन कपिल शर्मा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। उनके कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर अलग-अलग दिन तीन बार फायरिंग हुई। इन घटनाओं ने कपिल और उनके फैस के दिलों में डर बिठा दिया था। बताया गया कि इन हमलों की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्रॉई से जुड़े लोगों ने ली थी।



सलमान खान

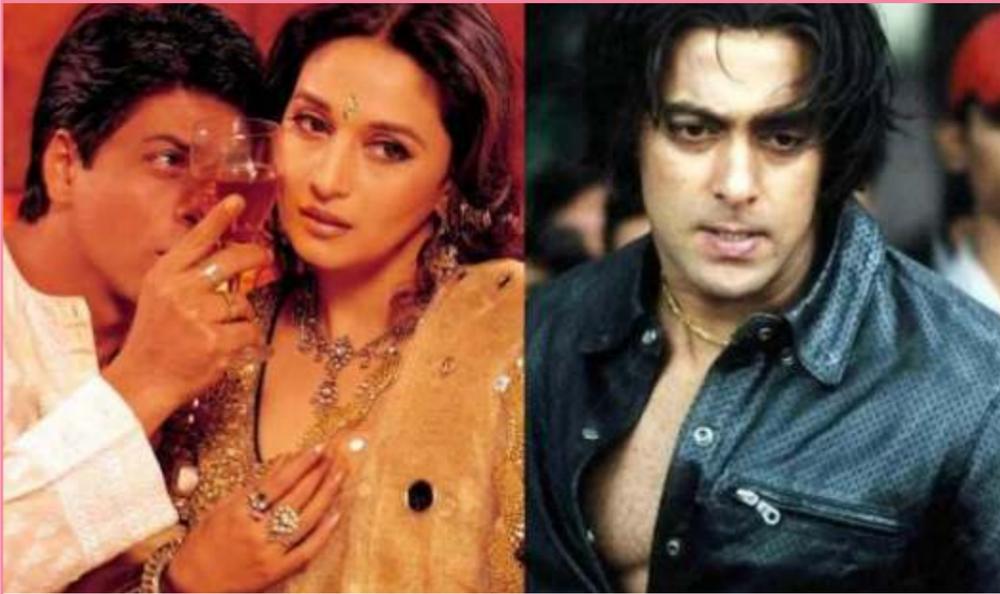
सलमान खान के घर के बाहर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग की घटना भी काफी चर्चा में रही। मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अज्ञात हमलावरों ने गोलियां चलाई थीं। उस वक्त सलमान खान घर में ही मौजूद थे। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई, इस मामले में भी बिश्रॉई गैंग का नाम सामने आया था।



एपी डिल्लों

पंजाबी गायक एपी डिल्लों भी इससे अछूते नहीं रहे। सितंबर 2024 में कनाडा स्थित उनके घर के बाहर फायरिंग की घटना सामने आई थी। इस मामले में कनाडा पुलिस ने जांच की और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हुआ था, जिसने फैस को चिंता में डाल दिया।

वैलेंटाइन मंथ स्पेशल: फिर से रही हैं 'देवदास' और 'तेरे नाम'



फरवरी को प्यार का महीना कहा जाता है और यह मंथ लवर्स के लिए काफी खास होता है।

क्योंकि इसी महीने में वैलेंटाइन डे पर कपल्स अपने प्यार का इजहार करते हैं। ऐसे में फिल्ममेकर्स वैलेंटाइन मंथ को और भी स्पेशल बनाने की तैयारी में हैं। और लवर्स को फिर से प्यार का जादू बिखेरे वाली क्लासिक फिल्मों को तोहफा देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं फरवरी में कौन-कौन सी मूवीज थिएटर में फिर से रिलीज होने वाली हैं।

फरवरी में 3 फिल्में होंगी री-रिलीज

शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म देवदास 6 फरवरी को री-रिलीज होगी। जबकि सलमान खान की तेरे नाम 27 फरवरी को सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देगी। अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और विवेक ओबेरॉय स्टारर फिल्म 'युवा' 20 फरवरी को री-रिलीज होगी।

24 साल बाद देवदास की वापसी

संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनी देवदास 12 जुलाई 2002 को रिलीज हुई थी। फिल्म में देव बने शाहरुख, पारो के रूप में ऐश्वर्या राय और चंद्रमुखी के किरदार में माधुरी दीक्षित ने फैस का दिल जीत लिया था। अब 24 साल बाद देवदास फिल्म फिर से थिएटर में लौट रही है। 6 फरवरी 2026 को इसे री-रिलीज किया जाएगा।

'तेरे नाम' बिखेरेगी जादू

2003 में रिलीज हुई 'तेरे नाम' फिल्म को सलमान खान के करियर का माइलस्टोन माना जाता है। सतीश कौशिक के डायरेक्शन में बनी इस रोमांटिक ड्रामा मूवी में सलमान खान ने राधे का किरदार निभाया था। भूमिका चावला के साथ उनकी केमिस्ट्री ने दर्शकों को दिल जीत दिया था। तेरे नाम फिल्म के गाने जैसे 'तुमसे कोई प्यार' और टाइटल ट्रैक आज भी हिट हैं। यह फिल्म 27 फरवरी 2026 को PVR-आइनाक्स थिएटर में री-रिलीज होगी।

20 फरवरी को री-रिलीज होगी 'युवा'

मणिरत्नम की फिल्म 'युवा' 20 फरवरी को री-रिलीज होगी। इस क्राइम थ्रिलर फिल्म में अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, अभिषेक बच्चन हैं। फिल्म में युवाओं की बगावत दिखाई गई है।

'जेलर 2' में शाहरुख निभाएंगे अहम किरदार



बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान की फिल्मों का क्रेज तो हमने बॉक्स ऑफिस पर हमेशा से ही देखा है। फैस उनके नए-नए प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट का इंतजार ही करते रहते हैं। 'किंग' के अनाउंसमेंट के बाद अब खबरें हैं कि शाहरुख खान रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में भी कैमियो करने वाले हैं। इतना ही नहीं इस फिल्म में शाहरुख का किरदार भी अहम रहने वाला है। रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' की मैसिव सक्सेस को देखते हुए, मेकर्स इसका दूसरा पार्ट भी लेकर आ रहे हैं। 'जेलर 2' पहले पार्ट से कहीं ज्यादा एक्साइटमेंट लेकर आ रहा है।

इस फिल्म में शाहरुख खान रजनीकांत के करीबी दोस्त की भूमिका निभाने वाले हैं। ये किरदार इस तरह से दिखाया जाने वाला है जिस पर रजनीकांत का किरदार अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा करता है। अब इस खबर

से फैस काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं इतना ही नहीं 'जेलर 2' में कई स्टार स्टडेड कैमियो हमें नजर आने वाले हैं, जिसके चलते फैस के बीच इसका क्रेज भी बहुत ज्यादा है। शाहरुख खान के अलावा खबरों की मानें तो फिल्म में विजय सेथुपति भी कैमियो करते नजर आएंगे। इसके अलावा खबरें हैं कि और भी कई स्टार्स इस फिल्म में कैमियो कर सकते हैं, जैसे विद्या बालन, बालाकृष्णा, नागार्जुन और मिथुन चक्रवर्ती। वैसे आपको ये भी बता दें कि शाहरुख खान के इस फिल्म में कैमियो की पोल मिथुन ने ही सबसे पहले खोली थी। बता दें कि 'जेलर 2' का निर्देशन नेलसन दिलिपकुमार कर रहे हैं, ऐसे में ये एक हार्दवोल्टेज एक्शन ड्रामा फिल्म हो सकती है। इस फिल्म को लेकर पहले पार्ट से भी ज्यादा क्रेज है। साल 2023 में आई रजनीकांत स्टारर 'जेलर' को उस समय बहुत पसंद किया गया था।

'मिर्जापुर द फिल्म' की शूटिंग हुई पूरी

भारत की सबसे फेमस और सबकी फेवरिट वेब सीरीज में से एक मिर्जापुर के बड़े पर्दे पर लौटने को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत और पुनीत कृष्णा द्वारा निर्मित मिर्जापुर: द फिल्म भारत की सबसे बड़ी क्राइम-थ्रिलर ओटीटी फ्रैंचाइजी मिर्जापुर का फिल्मी वर्जन है। जब से मिर्जापुर: द फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है, तब से ही फैस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इसी बीच प्रोड्यूसर ने एक बड़ा और रोमांचक अपडेट दिया है। मिर्जापुर: द फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिल्म का लास्ट शेड्यूल ऑफिसियल तौर पर रैप हो चुका है। प्रोड्यूसर्स ने सोशल मीडिया पर फ्रैंचाइजी के



दमदार और रोमांचक थीम म्यूजिक के साथ एक पोस्ट शेर कर रहे हुए रैप की अनाउंसमेंट की। इसके अलावा, मिर्जापुर: द फिल्म ने ऑरमैक्स सिनेमैटिक्स की मोस्ट अवेटेड हिंदी फिल्मों की सूची में भी अपनी जगह बना ली है।

जनजातीय जीवन कला में भील लोक चित्र



स्वाति आनंद

जनजातीय या कहे आदिवासी समाज का आध्यात्मिक जीवन गहरे मिथकों से जुड़ा होता है। यह मिथक बाह्य दृष्टि से भले ही सरल, रहस्यमय अथवा अव्यवस्थित प्रतीत हों, परंतु उनके भीतर जीवन के गहन अर्थ और आस्थाएँ निहित होती हैं। इन्हीं मिथकों के आधार पर जनजातीय जीवन संचालित और मर्यादित होता है। मिथक उनके लिए केवल कथाएँ नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और परंपरा के संवाहक होते हैं, जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से हस्तांतरित होते रहते हैं। कितनी पीढ़ियाँ से न जाने हमने अपनी कथाओं में जीवन दर्शन को सहेज कर रखा है जो हमें सिर्फ नियम के साथ प्रकृति से जुड़ना ही सिखाती है, जल जंगल

जमीन यह सिर्फ आदिवासी समझ ही क्यों करता है क्या विशिष्ट समाज को इसे सहेजने की जरूरत नहीं महसूस पड़ती हमने अपनी आज फिर चेतना में जल जंगल जमीन के प्रति अपने कर्तव्य को कल के माध्यम से भी सहेजना सीखा है।

जनजातीय कला इसी मिथकीय चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति है। यह कला किसी प्रदर्शन या विलास की वस्तु नहीं, बल्कि जीवन की सहज आवश्यकता है। चित्रकला, नृत्य, संगीत, शिल्प अथवा लोकगीत सभी कलारूप उनके दैनिक जीवन से गहराई

से जुड़े होते हैं। जनजातीय चित्रों में पशु-पक्षी, वृक्ष-वनस्पतियाँ, सूर्य, चंद्रमा और मानव आकृतियाँ बार-बार दिखाई देती हैं, क्योंकि यही उनका संसार है, यही उनकी स्मृति और अनुभव का विस्तार है। इन कलाओं में यथार्थ का हूबहू चित्रण नहीं, बल्कि स्मृति और अनुभूति का चित्रांकन होता है। रंगों और रेखाओं का प्रयोग प्रतीकात्मक होता है-उजले, गाढ़े और चटख रंग जीवन की ऊर्जा और उल्लास को व्यक्त करते हैं। जनजातीय कलाकार किसी बड़े-बड़े चित्रकारों की तरह प्रशिक्षित नहीं होते, फिर भी उनकी कला में मौलिकता, संतुलन और लय का अद्भुत सौंदर्य दिखाई देता है। जनजातीय समाज में परंपरा और कला सबके लिए समान रूप से सुलभ होती है। यहाँ कला किसी एक वर्ग या व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। यही कारण है कि जनजातीय संस्कृति को लोकधर्म की संज्ञा दी जा सकती है- एक ऐसा धर्म, जहाँ कला, विश्वास और जीवन एक-दूसरे से अलग नहीं, बल्कि परस्पर पूरक हैं। कला यहाँ स्वतंत्र सत्ता न होकर जीवन की अभिव्यक्ति है। इस प्रकार जनजातीय कला और जीवन हमें यह सिखाते हैं कि सृजन का मूल उद्देश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। आधुनिक सभ्यता के यांत्रिक और उपभोक्तावादी दृष्टिकोण के बीच जनजातीय कला हमें प्रकृति, परंपरा और मानवीय संवेदना से जुड़ने का मार्ग दिखाती है।



पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय ने लिखा पहला छत्तीसगढ़ी नाटक

स्वराज्य करुण

आज से लगभग 120 वर्ष पहले उनके द्वारा लिखित नाटक 'कलिकाल' को छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला नाटक माना जाता है, जो वर्ष 1905 में प्रकाशित हुआ था। साहित्यकार होने के साथ-साथ पाण्डेय जी उपन्यासकार, इतिहासकार और पुरातत्वविद भी थे। पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय का जन्म महानदी के किनारे स्थित ग्राम बालपुर में 4 जनवरी 1887 को हुआ था। उनका निधन 8 नवम्बर 1959 को हुआ।



छत्तीसगढ़ की महान साहित्यिक विभूतियों में पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय का नाम अमिट अक्षरों में दर्ज है। आज से लगभग 120 वर्ष पहले उनके द्वारा लिखित नाटक 'कलिकाल' को छत्तीसगढ़ी भाषा का पहला नाटक माना जाता है, जो वर्ष 1905 में प्रकाशित हुआ था। साहित्यकार होने के साथ-साथ पाण्डेय जी उपन्यासकार, इतिहासकार और पुरातत्वविद भी थे। पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय का जन्म महानदी के किनारे स्थित ग्राम बालपुर में 4 जनवरी 1887 को हुआ था। उनका निधन 8 नवम्बर 1959 को हुआ। उनका गाँव बालपुर पहले बिलासपुर जिले में था, जो अब जांजगीर-चाम्पा जिले में स्थित है और रायगढ़ जिले से भी लगा हुआ है। पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय, आधुनिक हिन्दी कविता में छायावाद के प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध हुए। लोचन प्रसाद जी हिन्दी, छत्तीसगढ़ी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी और ओड़िया भाषाओं के विद्वान थे। विभिन्न साहित्यिक विधाओं में उनकी लगभग 40 पुस्तकों का प्रकाशन हुआ, जिनमें तीन ओड़िया भाषा और चार अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें भी शामिल हैं। आप इतिहास और पुरातत्व के भी गंभीर अध्येता थे। उन्होंने वर्ष 1923 में छत्तीसगढ़ गौरव प्रचारक मंडली की स्थापना की, जो आगे चलकर महाकेशल इतिहास परिषद के रूप में विकसित हुई। छत्तीसगढ़ के इतिहास और पुरातत्व को देश-दुनिया के सामने लाने के लिए उन्होंने निरंतर शोध और परिश्रम किया। पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक चेतना के ऐसे स्तंभ थे, जिनका योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देता रहेगा।

इतिहास म दर्ज रायपुर शहर के गौरव काल

डा रमेशनाथ मिश्र

सन 1877 ले 1879 तक के बेरा आय जऊन रायपुर बर बड़ गौरव के बात आय। 14 ले 16 बछर के उमर म नरेन्द्रनाथ दत्त के मन में जउन विचार चिंतन छत्तीसगढ़ में रहीके अइस, इहां के पहाड़, नदिया, मंदिर ल देख के सोचीन, गुनीन संग म मंदरस माछी के छत्ता ल बड़ला गाड़ी म आत जात रद्दा म जब पहाड़ में देखीस त उकर मन में विचार आय रीहिस, जउन उनकर चिंतन, दर्शन के रद्दा डहर आगू चल के लेगिस अइसन सियान मन गोठियइन। अपन ददा के

संगवारी मन के बैठक संग संगीत के गोठबात म इहु रहीके गोठियाय, सब इन ल ताजुब लगय के अतका बड़ लइका दुनिया भर के गोठ ल कहां ले अउ कइसे जानथे। उनकर ददा ह वकील रीहिन अउ छत्तीसगढ़ मुकदमा के सिलसिला में आय रीहिन।

रायपुर ह एक जमाना म बड़ सुघर शहर रीहिस। सात समुंदर पार ले जउन घूमैया फिरैया मन आवय ओमन बड़ प्रशंसा करे, जइसे ब्लंट, बेगलर, साधु चरणदास।



अनेक महत्व का गांव है आलोर

घनश्याम नाग

बस्तर की प्राचीन राजधानी बड़े डोंगर के पूर्व दिशा में आलोर नामक गांव है। आलोर गांव को बड़े डोंगर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आलोर के लिंगई मड्डा में लिंगई माता विराजमान है। पहाड़ी को स्थानीय गोंडी भाषा में मद्रा कहा जाता है। मद्रा के आसपास शैलचित्र, देव हाट, महिषासुर राक्षस के विशालकाय पैर के चिन्ह एवं जलहरि युक्त शिवलिंग है। महिषासुर राक्षस गुफाओं में निवास करता था तथा घने जंगलों एवं पहाड़ियों में विचरण करता था। केशकाल घाटी से लेकर ग्राम बड़े डोंगर तक पहाड़ियों की

लंबी श्रृंखला है। घने जंगलों के बीच इन पहाड़ियों में अनेक गुफाएं और झरने भी हैं।

यहां की भौगोलिक और प्राकृतिक परिवेश को देखकर ऐसा लगता है कि शास्त्रों में वर्णित महिषासुर का विचरण स्थल भी इन्हीं पहाड़ियों, गुफाओं एवं घने जंगलों में रहा होगा। दंत कथाओं में यही कहा जाता है कि मां दुर्गा महिषासुर राक्षस को इन्हीं दुर्गम पहाड़ियों से खदेड़ते हुए भैंसा दौड़ डोंगरी तक ले गईं। महिषा इंड पहाड़ी में, महिषासुर मर्दिनी एवं महिषासुर राक्षस के बीच अंतिम महिमासुर संग्राम हुआ था।



बिन पानी सब सून...

छत्तीसगढ़ का वाटरलेवल ठीक रखने डबरी बनाने का फैसला



- जोगी डबरी की तर्ज पर विष्णुदेव डबरी बनेगी प्रदेश की उम्मीद
- जल स्रोत विहीन ग्रामों में जल संरक्षण-संवर्धन की कार्ययोजना
- डबरी निर्माण से किसानों के साथ भू-जल स्तर की सुधरेगी स्थिति

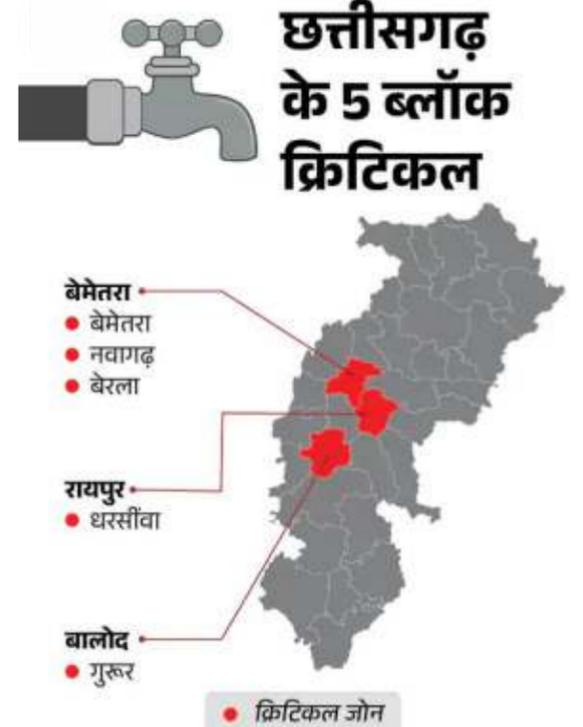
विशेष संवाददाता/शेख आबिद
मोबाईल नंबर 8109802829

स्रोत विहीन और संभावित जल समस्या वाले क्षेत्रों में अब भू-जल स्तर खतरनाक ग्राफ पर है। खासकर राजधानी रायपुर समेत आसपास के इलाकों में जल स्तर गंभीर स्थिति में है। इंडस्ट्रियल इलाकों में पानी का बेतहाशा दुरुपयोग, हादसों और भयानक अग्निकांड के वक्त पानी का अपर्याप्त बंदोबस्त खतरनाक संकेत है। शासन के पास औद्योगिक क्षेत्रों में ऐसी वारदात में आग पर काबू पाने के लिए जो संसाधन हैं वह या तो बहुत दूर हैं या फिर उपयुक्त नहीं हैं। फैक्ट्रियों में लगने वाली आग पर काबू पाने का इंतजाम चंद बड़े उद्योगों के पास है और शासन इन्हीं के भरोसे भी है।

शहर सत्ता/रायपुर। जल स्रोत विहीन ग्रामों में जल संरक्षण एवं संवर्धन की कार्ययोजना तैयार करने के लिए आज दरकार है। प्रदेश में गिरते जल स्तर के लिए शासन की योजना और प्रयास नाकाफी हैं। अभी तो गर्मी शुरू भी नहीं हुई है और हादसों ने सरकारी इंतजामों की कलाई खोलकर रख दिया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ का वाटरलेवल ठीक रखने डबरी बनाने का फैसला किया था। तब उसे बोलचाल में जोगी डबरी कहा जाता था। जोगी ने अपने कार्यकाल के तीसरे साल में यह सोचकर डबरी की प्लानिंग की थी कि अभी तो उन्हें लंबी पारी खेलनी है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी पारी को जल्दी समेट दी। जोगीजी जो काम नहीं कर पाए, अब विष्णुदेव सरकार उसे पूरा करने जा रही है। लेकिन यह योजना कब और कितनी ईमानदारी से वक्त पर पूरी होगी इसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। मनरेगा मद से गांव-गांव में 12 हजार डबरी बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। जाहिर है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह पानी का लेवल डाउन हो रहा, उसमें ये डबरी बड़ी कारगर होगी।

डबरी से गिरता भू-जल स्तर सुधरेगा

छत्तीसगढ़ में गिरते भू-जल स्तर को सुधारने और सिंचाई सुविधा बढ़ाने के लिए मनरेगा (MGNREGA) के तहत बड़े पैमाने पर डबरी (छोटा तालाब) निर्माण का फैसला लिया गया है। इस योजना के तहत किसानों की निजी भूमि पर डबरी बनाकर जल संरक्षण, रबी फसल को बढ़ावा और मत्स्य पालन जैसे रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं। राज्य भर में मनरेगा के माध्यम से किए जा रहे ऐसे जल संरक्षण कार्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।



डबरी ने बदल दी किसान बसंत की जिंदगी

प्रत्यक्ष उदाहरण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के विकासखण्ड शंकरगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत दोहना के निवासी श्री बसंत हैं, जिनके जीवन में मनरेगा के तहत डबरी (फार्म पोंड) निर्माण से सकारात्मक बदलाव आया है। श्री बसंत बताते हैं कि पहले वे केवल वर्षा के पानी पर निर्भर थे, जिससे बेमौसम बारिश और पानी की कमी के कारण खेती करना कठिन हो जाता था और पर्याप्त फसल नहीं मिल पाती थी। किसानों की स्वीकृति के पश्चात् उनकी भूमि पर कृषि डबरी का निर्माण पूर्ण हुआ। 2.5 एकड़ भूमि वाले श्री बसंत अब सिंचाई सुविधा के कारण खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलें ले पा रहे हैं, जिससे उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डबरी निर्माण से न केवल खेतों की सिंचाई सुचारु हुई है, बल्कि पशुओं के लिए पेयजल की व्यवस्था भी संभव हो पाई है। इसके साथ ही श्री बसंत ने डबरी में मत्स्य पालन की शुरुआत की है, जिससे अतिरिक्त आय की संभावना भी बनी है।



कार्य के पूर्व बदलाव

- आजीविका का साधन न होना।
- स्थल का कोई उपयोग नहीं हो रहा था।
- सिंचाई हेतु जल का अभाव।

कार्य के बाद बदलाव

- आजीविका का साधन प्राप्त होने से जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
- स्थल का सदुपयोग हुआ है।
- खेतों में सिंचाई की सुविधा।

जोगी डबरी नहीं, विष्णुदेव डबरी

छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने आज से 25 साल पहले छत्तीसगढ़ का वाटरलेवल ठीक रखने डबरी बनाने का फैसला किया था। तब उसे बोलचाल में जोगी डबरी कहा जाता था। जोगी ने अपने कार्यकाल के तीसरे साल में यह सोचकर डबरी की प्लानिंग की थी कि अभी तो उन्हें लंबी पारी खेलनी है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता ने उनकी पारी को जल्दी समेट दी। जोगीजी जो काम नहीं कर पाए, अब विष्णुदेव सरकार उसे पूरा करने जा रही है। मनरेगा मद से गांव-गांव में 12 हजार डबरी बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। जाहिर है, छत्तीसगढ़ में जिस तरह पानी का लेवल डाउन हो रहा, उसमें ये डबरी बड़ी कारगर होगी।



ईमानदार प्रयास की जरूरत

- निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण तरीके से कार्य जाये
- भूमिगत जल का उपयोग पेयजल के लिए ही किया जाये
- ग्रामीणों को कुंआ और डबरी निर्माण के लिए करें प्रोत्साहित
- जिन शहरों का वाटर लेवल तेजी से गिर रहा वहां भी हो ताल-तल्लैया
- खेतों में सिंचाई की सुविधा।